दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

आज का विचार

भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव होता है... जो बोया है वह ही निकलना स्वाभाविक है।

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ I बुधवार, 27 मई, 2026 वर्ष 24, अंक 127, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

मुख्यमंत्री योगी ने नगर निगम लखनऊ की 413 करोड़ की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

महापौर सुषमा खर्कवाल के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को लखनऊवासियों को मिली विकास की सौगात

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने पहली बार प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में मेयर की सीट भाजपा की झोली में डालीं। सभी नगर निगमों में भाजपा का बोर्ड बना। इसका परिणाम रहा कि नगर निगम ने तीन वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए, विकास व स्वच्छता का मॉडल दिया। हमें पिछली सरकारों के पापों के गड्ढों को भरने, भ्रष्टाचार के कूड़े को साफ करने में समय भी लगा। विकास पर खर्च होने वाला पैसा जनता का है। इसे मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं दे रहे, बल्कि केवल उसका उचित नियोजन कर रहे हैं। जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, प्रेरणा है।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ नगर निगम में महापौर सुषमा खर्कवाल के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को लखनऊवासियों को विकास की सौगात दी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 413 करोड़ की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण किया। स्वच्छ-सुंदर-समर्थ लखनऊ से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री योगी ने सभी 17 नगर निगमों के महापौर, 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायतों के चेयरमैन तथा लगभग 14000 पार्षदों को तीन वर्ष का कार्यकाल संपन्न होने पर शुभकामनाएं दी।

योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में तीसरा स्थान मिला। इसे पहले स्थान पर लाना है। यह केवल महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकें, गीला-सूखा कूड़ा अलग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। नालियों में कूड़ा न फेंकें और सरकारी संपत्तियों का नुकसान भी न करें। लोग कहते हैं कि लखनऊ बहुत साफ-सुथरा है, जब सरकार की कार्यपद्धति साफ-सुथरी होती है तो ऐसा ही होता है। मंत्री, महापौर, पार्षद, पूरी कार्यकारिणी, अधिकारी, सुपरवाइजर तथा सफाई कर्मचारी, सब जुटते हैं तो स्वच्छता दिखाई देती है।

मुख्यमंत्री ने ढाई करोड़ की कार से आकर गमला चोरी करने वालों पर कटाक्ष किया और कहा कि सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 45 रुपये का गमला खरीद लेते तो सम्मान भी बना रहता और शहर भी सुंदर दिखता। योगी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उदाहरण दिया और कहा कि जहां 30 वर्षों से कूड़ा डंप होता था, वह अब बेहतरीन स्थल है। आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल ही नहीं, ग्रीन कॉरिडोर व मेट्रो समेत हर प्रकार की जन-सुविधाएं हैं।

योगी ने कहा कि 2017 से पहले सपा सरकार में गरीब के लिए मकान स्वीकृत नहीं हुए। उनकी योजनाएं गरीबों, नौजवानों के लिए नहीं थीं। हमने चेहरा, जाति, क्षेत्र, मत-मजहब देखे बिना देश की चार जातियों (गरीब, युवा, महिला व किसान) को केंद्र में रखकर काम किया। सपा सरकार में शासन की योजनाओं का लाभ चुनिंदा परिवारों को मिलता था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।

योगी ने कहा कि ऊर्जा संकट वैश्विक बन चुका है। अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण सप्लाई लाइन बाधित हुई है। दुनिया के तमाम क्षेत्रों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जिस अमेरिका के पास अपने ऊर्जा के क्षेत्र हैं, वहां पेट्रोलियम पदार्थ के दाम दोगुने से अधिक हुए हैं। महंगाई चरम पर है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में लगातार इसे नियंत्रित किया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों के दाम दुनिया में बढ़ेंगे, सप्लाई चेन बाधित होगी तो उसका असर यहां भी पड़ेगा, लेकिन संकट के समय देश के साथ खड़े होने के बजाय देश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास अस्वस्थ मानसिकता का पर्याय है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गर्मी एकाएक बढ़ने से तमाम थर्मल पावर प्लांट ने अचानक शटडाउन ले लिया। उत्पादन पर असर पड़ा। 2017 तक यूपी में पीक पावर की सप्लाई 15-16 हजार मेगावाट रहती थी, आज यह 32-33 हजार मेगावाट पहुंच गई है। उस समय छह हजार मेगावाट उत्पादन था, जबकि आज 13 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। रिन्युवल एनर्जी का उत्पादन लगभग 10 हजार मेगावाट तक बढ़ा है, लेकिन हमारी आवश्यकता 33-35 हजार मेगावाट है। एलपीजी संकट को देखते हुए लोग खाना पकाने में इलेक्ट्रिक हीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की समस्या हर किसी की समस्या है। किसी के बहकावे में न आएं। जितनी आवश्यकता है, उतनी ही बिजली खपत करें।

उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले देश के हितैषी नहीं हैं। जब ये सत्ता में रहे तो आमजन के हित में कार्य नहीं किया।

पीएम मोदी के मार्गदर्शन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रदर्शन के नए आयाम स्थापित किए

खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र ने पहली बार 1.87 लाख करोड़ के कारोबार का आंकड़ा पार किया

एजेंसी
नई दिल्ली

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र ने बीते 12 वर्षों में विकास और परिवर्तन की अभूतपूर्व यात्रा तय की है। वित्त वर्ष 2025-26 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 1,87,105 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई, जो अब तक की सर्वाधिक बिक्री है और ग्रामीण भारत की बढ़ती उद्यमशीलता, आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त प्रमाण है। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल जैसे राष्ट्रीय अभियानों से प्रेरित होकर खादी आज केवल एक पारंपरिक उत्पाद नहीं, बल्कि नये भारत की आत्मनिर्भरता, स्वदेशी गौरव और ग्रामीण समृद्धि का जीवंत प्रतीक बन चुकी है। उत्पादन, विपणन और रोजगार सृजन के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान की है। नई दिल्ली के गांधी दर्शन, राजघाट स्थित कार्यालय में वित्त वर्ष 2025-26 के अनंतिम आंकड़े जारी करते हुए केवीआईसी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने कहा कि आयोग ने उत्पादन, बिक्री और रोजगार सृजन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 12 वर्षों में बिक्री में 501 प्रतिशत, उत्पादन में 380 प्रतिशत और रोजगार सृजन में 56 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

उत्पादों की बिक्री 1.87 लाख करोड़ रुपये के पार

अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने कहा कि केवीआईसी का यह सशक्त प्रदर्शन विकसित भारत@2047 के संकल्प को गति प्रदान करने के साथ-साथ भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी मार्गदर्शन, महात्मा गांधी की प्रेरणा तथा देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत करोड़ों कारीगरों की मेहनत को दिया। अध्यक्ष केवीआईसी ने बताया कि वित्त वर्ष 2013-14 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन जहां 26109 करोड़ रुपये था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में यह करीब पांच गुना बढ़कर 380 प्रतिशत के उछाल के साथ 125296 करोड़ रुपये पहुंच गया। जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में बिक्री जहां 31154 करोड़ रुपये थी, वहीं करीब छह गुना बढ़कर 501 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ यह वित्त वर्ष 2025-26 में 187105 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो कि अब तक की सर्वाधिक बिक्री है।

खादी वस्त्रों के उत्पादन और बिक्री में अभूतपूर्व वृद्धि

खादी वस्त्रों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। वर्ष 2013-14 में 811 करोड़ रुपये का उत्पादन बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 390 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,974 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं बिक्री 1,081 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 628 प्रतिशत वृद्धि के साथ 7,869 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री द्वारा खादी के सतत प्रचार-प्रसार का सकारात्मक प्रभाव इस क्षेत्र की बढ़ती स्वीकार्यता और बाजार विस्तार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन और बिक्री का नया रिकॉर्ड

ग्रामोद्योग क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। वर्ष 2013-14 में जहां ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन 25,298 करोड़ रुपये था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 380 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह बढ़कर 1,21,322 करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार बिक्री 30,073 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 496 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,79,236 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी ग्रामोद्योग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2013-14 में जहां इस क्षेत्र में 1.19 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 1.99 करोड़ के स्तर के करीब पहुंच गया है, जो ग्रामीण आजीविका सृजन में इस क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और घर-घर स्वदेशी जैसे अभियानों के प्रभाव से ग्रामोद्योग उत्पादों की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे यह क्षेत्र ग्रामीण उद्योगों के विस्तार, बाजार सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन का एक प्रमुख आधार बनकर उभरा है।

रोजगार सृजन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि

रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी केवीआईसी ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2013-14 में जहां खादी और ग्रामोद्योग से जुड़ी गतिविधियों में संचयी रोजगार 1.30 करोड़ था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में यह 56 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 2.04 करोड़ हो गया है, जो ग्रामीण आजीविका सृजन में केवीआईसी की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है।

घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार ने उच्चस्तरीय समिति गठित की

जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन भी करेगी समिति

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने तथा उससे निपटने के उपाय सुझाने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी, जिसे 11 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी।

सरकार द्वारा गठित इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। समिति में जनगणना आयुक्त के अलावा दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि सदस्य होंगे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फॉरेनर्स-1) समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। समिति को एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय इसके कार्यकाल को अधिकतम छह महीने तक बढ़ा सकेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला असामान्य जनसांख्यिकीय बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह विषय राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है।

सरकार के अनुसार, यह समिति देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलावों का वैज्ञानिक आकलन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और आवश्यक नीतिगत, विधायी तथा प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक उपाय सुझाएगी।

समिति जनसांख्यिकीय बदलावों से उत्पन्न चुनौतियों, विशेषकर घुसपैठ, सीमा पार गतिविधियों, असामान्य बसावट पैटर्न और संगठित प्रवासन जैसे कारणों का अध्ययन करेगी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का भी विश्लेषण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त समिति अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध तंत्र विकसित करने संबंधी सुझाव देगी। सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए संस्थागत व्यवस्था की सिफारिश भी समिति करेगी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करने के साथ-साथ समिति इस विषय से जुड़े अन्य आवश्यक उपायों की भी अनुशंसा कर सकेगी।

सीबीएसई पोर्टल 72 घंटे से अधिक समय से स्थिर, तकनीकी खामियों की जांच में जुटी टीम

एजेंसी
नई दिल्ली

आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि ने मंगलवार को कहा कि संस्थान और आईआईटी कानपुर के चार सदस्यीय दल ने सीबीएसई पोर्टल में हाल ही में आई गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें भुगतान विफलताएं और उत्तर पुस्तिका अपलोड करने से संबंधित आरोप शामिल हैं।

ह्यपीटीआई-भाषाह्न को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, कामकोटि ने कहा कि टीम ने सोमवार शाम को इस मुद्दे की जांच शुरू कर दी और प्राथमिक ध्यान व्यवधान के सटीक कारण का पता लगाने पर है। उन्होंने कहा, लगभग दो दिनों तक

समस्या बनी रही। तो इस विफलता का वास्तविक कारण क्या था? क्या यह कोई विकास संबंधी समस्या थी, तकनीकी समस्या थी, या फिर कोई साइबर हमला था? क्योंकि कुछ भी संभव है। इसलिए हम यही पता लगाना चाहते हैं ताकि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का पोर्टल पिछले 72 घंटों से अधिक समय से स्थिर बना हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर को निर्देश दिया कि वे सीबीएसई को त्रुटिरहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करें।

कामकोटि ने कहा कि सीबीएसई द्वारा ह्यऑन-स्क्रीन मार्किंगह्न (ओएमएस) शुरू करने का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है, जिससे छात्रों को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को देखने और यह समझने की सुविधा मिलेगी कि उनके अंक कहां से काटे गए हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सीबीएसई ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और साथ ही यह भी जोड़ा कि इस प्रणाली से काफी अधिक पारदर्शिता आती है। उन्होंने कहा, लेकिन कहीं न कहीं कोई भुगतान प्रक्रिया या कोई गेटवे विफल हो गया है। टीम इस मुद्दे की गहराई से जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि एक ऐसा मजबूत मंच क्या हो सकता है जो भविष्य में हमें इस प्रकार की विफलता का सामना न करने दे। आईआईटी मद्रास के निदेशक ने कहा कि टीम सबसे पहले वेबसाइट का पूर्ण परीक्षण करेगी और प्लेटफॉर्म को संभालने वाले डेवलपर्स को सुझाव और सिफारिशें देगी, साथ ही यह भी जांच करेगी कि शुल्क लेनदेन के दौरान सीबीएसई पोर्टल और भुगतान प्रणाली कैसे परस्पर क्रिया करते हैं।

शिवराज की पुस्तक अपनापन का लोकार्पण, नायडू सहित कई राज्यों के सीएम रहे मौजूद

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को एक समारोह में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन का लोकार्पण किया। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, कार्यशैली और उनके साथ बिताए गए 35 वर्षों के अनुभवों पर लिखी है। पुस्तक के लोकार्पण अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।

समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि जब कभी प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा होती थी, तब वे कहा करते थे कि मोदी का अर्थ है मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया और आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें यह भाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान विश्व मंच पर अधिक सशक्त हुई है। वेंकैया नायडू ने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय सभ्यता, भारतीयता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को वैश्विक स्तर पर नई स्वीकृति मिली है।

पद्म पुरस्कारों का उल्लेख कर वेंकैया नायडू ने कहा कि पहले ऐसे सम्मानों को अक्सर कुछ चुनिंदा प्रतिष्ठित वर्गों तक सीमित समझा जाता था लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की सोच रिकॉग्नाइज द अनरिकॉग्नाइज्ड की है, यानी उन साधारण लोगों को भी सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने चुपचाप समाज और राष्ट्र के लिए असाधारण योगदान दिया है। उन्होंने विशेष प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब किसानों जैसे मेहनतकश लोगों को भी राष्ट्रीय सम्मान मिलने लगे हैं और यह बदलती सोच भारत के सामाजिक सम्मान-क्रम को अधिक न्यायपूर्ण बनाती है। यह नेतृत्व का वही रूप है जो राष्ट्र निर्माण में सामान्य जन की भूमिका को केंद्र में रखता है।

निजी वाहनों के प्रयोग में कमी के लिए हर गांव व शहर को बस सेवा से जोड़ा जाए: नायब सिंह सैनी

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा विजन-2047 के अंतर्गत परिवहन विभाग के अगले 5 वर्षों के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पेट्रोल व डीजल की खपत को कम करने के लिए निजी वाहनों के प्रयोग में कमी लाना जरूरी है और यह तभी होगा जब अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी बसों की सुविधा पहुंचेगी। इसलिए परिवहन विभाग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बढ़ी हुई आबादी तथा भविष्य में पैदा होने वाली मांग के अनुरूप पूरे प्रदेश का रूटमैप बनाए और रिवाइज रूट प्लान के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा गांवों व शहरों को बस सुविधा से जोडे।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 के अंतर्गत परिवहन विभाग के अगले 5 वर्षों के रोडमैप व कार्ययोजना के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस दौरान उन्होंने भविष्य में मांग के अनुरूप परिवहन विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली की नई तकनीकों व योजनाओं की भी समीक्षा की और इनके संबंध में अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि परिवहन विभाग उचित प्रबंधन करें तो बसों की कमी भी दूर हो सकती है और अधिक से अधिक लोगों तक परिवहन सुविधाओं तक पहुंच भी सुनिश्चित की जा सकती है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि समय के साथ प्रदेश में मौजूद लगभग 6500 गांवों और शहरी क्षेत्र में आबादी तो बढ़ी है लेकिन परिवहन विभाग की बसों की पहुंच इसकी तुलना में उतनी नहीं बढ़ सकी है। विभाग नई जरूरतों के अनुसार पूरे प्रदेश का रूट प्लान तैयार करे और हर गांव तक बसों की पहुंच सुनिश्चित करने की योजना तैयार करे ताकि विद्यार्थियों व महिलाओं के साथ-साथ कामकाजी व्यक्ति भी बसों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और निजी वाहनों के प्रयोग में कमी आए। गांवों का सर्कल बनाकर आपस में बसों से जोड़ा जाए। जरूरत हो तो इसके लिए पुरानी पॉलिसी में संशोधन भी किया जा सकता है। सरकार परिवहन विभाग को ऐसा बनाना चाहती है कि एक साल बाद हम कह सकें कि हमारा एक भी गांव ऐसा नहीं है जो बस सेवा से न जुड़ा हो।

शहरों के भीतर चलाई जाएं लोकल बसें

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शहरों के आंतरिक हिस्सों में लोकल बसें चलती थी जो शहर के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ती थीं लेकिन अब ऐसी बसों की संख्या बहुत कम हो गई है जबकि शहरी क्षेत्रों का काफी विस्तार हो गया है। इससे शहरों के बाहरी हिस्सों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के कामगारों को अपने वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी शहरों में प्रमुख अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थानों तक सिटी बसों की पहुंच सुनिश्चित की जाए। गुरुग्राम, फरीदाबाद व सोनीपत जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों के लिए विशेष बसें चलाई जाएं और मैट्रो स्टेशनों तथा बस स्टैंडों तक मिनी बसें चलाई जाएं।

रेलवे की तरह बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी बसों को रेलवे की तर्ज पर ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए ताकि यात्री ऐप के माध्यम से देख सकें कि कौन सी बस इस समय कहां है और किस स्टॉप पर किस समय पहुंचेगी। प्रत्येक बस की डिपो से चलने के बाद रियल टाइम लोकेशन दिखाई देनी चाहिए। इसी प्रकार बसों में सीसीटीवी भी लगवाए जाएं जो कंट्रोल रूम से जुड़ें हों। बसों में पैनिक बटन भी लगवाए जाएं ताकि आपात स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

एक साल में 10 नए इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनेंगे

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाएं। इनकी चार्जिंग के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रदेश में 10 नए इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनाए जाएंगे। बस स्टैंड पर सवारियों के लिए जहां इलेक्ट्रिक बस खड़ी होगी वहीं पर उनके चार्जिंग प्वाइंट लगवाए जाएं। बस में सवारियों के चढ़ने और उनकी टिकट काटने के दौरान ही बसों को चार्ज करने की व्यवस्था की जाए। हर जिले व हर शहर में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएं। इसी प्रकार प्रदेश के अधिक से अधिक हिस्सों में पीपीपी मोड में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करवाए जाएं।

राज्यपाल ने धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का किया आह्वान, मां ज्वाला देवी के दरबार में टेका माथा

एकीकृत धार्मिक सर्किट से बदलेगी बुनियादी ढांचे की सूरत और बढ़ेगा रोजगार

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला/कांगड़ा

हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मंगलवार को अपनी पत्नी बिंदु गुप्ता के साथ विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ज्वाला देवी मंदिर में शीश नवाया। इस दौरान राज्यपाल ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और पवित्र ज्योतियों के दर्शन कर देश व प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए राज्यपाल ने 'देवभूमि' हिमाचल प्रदेश की अपार आध्यात्मिक और पर्यटन क्षमता को रेखांकित किया।

उन्होंने राज्य के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए एक एकीकृत और सुव्यवस्थित 'धार्मिक पर्यटन सर्किट' बनाने की पुरजोर वकालत की। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुरम्य पहाड़ियों में अध्यात्म की एक अद्भुत ऊर्जा समाहित है। यहाँ की प्राचीन

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान

विरासत और आस्था के केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर वैश्विक स्तर पर उभारा जा सकता है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को एक नए और आधुनिक ढांचे की सख्त जरूरत है। उन्होंने एक व्यापक कार्ययोजना के तहत राज्य के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठों–मां ज्वाला देवी, ब्रजेश्वरी देवी (कांगड़ा), चिंतपूर्णी (ऊना), नैना देवी (बिलासपुर), और चामुंडा देवी सहित विभिन्न बौद्ध मठों, प्राचीन मंदिरों और सिख धार्मिक स्थलों को एक ही सर्किट के अंतर्गत जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। इस सर्किट के निर्माण का मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों के लिए सुगम संपर्क (कनेक्टिविटी), बेहतर सड़कें, परिवहन के आधुनिक साधन और विश्वस्तरीय ठहरने की

व्यवस्था करना है। राज्यपाल ने कहा कि जब इन पवित्र स्थलों पर आधुनिक सुविधाएं और सुगम मार्ग उपलब्ध होंगे, तो देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होगा। राज्यपाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल धार्मिक पर्यटन का विस्तार करना ही नहीं, बल्कि इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। पर्यटन बढ़ने से होटल व्यवसाय, स्थानीय हस्तशिल्प, गाइड, परिवहन और छोटे दुकानदारों की आय में वृद्धि होगी, जिससे हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अत्यधिक मजबूती मिलेगी।

यह कदम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में भी मील का पत्थर साबित होगा। अपनी यात्रा के अनुभव साझा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मां ज्वाला देवी का यह दरबार अनादि काल से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ बिना किसी तेल या बाती के निरंतर प्रज्वलित रहने वाली नौ पावन ज्योतियां ईश्वर की जीवंत सत्ता और प्रकृति के चमत्कार का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ अद्वितीय आध्यात्मिक संपदा से भी संपन्न है।

कांगड़ा घाटी के ऐतिहासिक संदर्भों और अन्य शक्तिपीठों का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कांगड़ा की मां ब्रजेश्वरी, चामुंडा धाम और चिंतपूर्णी जैसी पावन भूमि का अपना एक विशेष धार्मिक इतिहास है। इन सभी स्थलों पर सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। इसके अतिरिक्त, राज्य के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित प्राचीन बौद्ध मठ (जैसे लाहौल-स्पीति और किन्नौर के मठ) तथा ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। राज्यपाल का मानना है कि इन सभी विविध आध्यात्मिक केंद्रों को एक धागे में पिरोकर हम दुनिया के सामने हिमाचल प्रदेश को 'अध्यात्म के सबसे बड़े केंद्र' के रूप में पेश कर सकते हैं।

नौतपा की तपिश में लोकतंत्र का उत्साह, 103 साल की बुजुर्ग महिला समेत उम्रदराज मतदाताओं ने डाले वोट

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में नौतपा के दूसरे दिन पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच मंगलवार को गांवों में लोकतंत्र का उत्सव देखने को मिला। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज लू चलने का अलर्ट जारी किया है। सुबह होते ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए ग्रामीण इलाकों में मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। कई जगह लोग सुबह सात बजे से पहले ही मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच गए थे ताकि बढ़ती गर्मी से पहले वोट डाल सकें। पहाड़ों के गांवों में आज चुनावी माहौल किसी त्योहार जैसा दिखाई दिया।

प्रदेश की 1,293 पंचायतों में पंचायत प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। करीब 16 लाख मतदाता अपने गांव की सरकार चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। मतदान बैलेट पेपर से कराया जा रहा है और दोपहर तीन बजे तक मतदान जारी रहेगा। इस बार पंचायत चुनाव में

सबसे ज्यादा चर्चा बुजुर्ग मतदाताओं के उत्साह की हो रही है। शिमला जिला की ग्राम पंचायत झगटान में 103 वर्षीय बुजुर्ग महिला मतदान केंद्र पहुंचीं तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखते रह गए। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका मतदान के प्रति उत्साह लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। शिमला जिला के चिक्सर पोलिंग बूथ पर 99 वर्षीय सूरत ने वोट डालकर लोकतंत्र में भागीदारी की मिसाल पेश की। वहीं ढाकगांव पंचायत के बूथ खरोट-2 में चिवाड़ी गांव के 88 वर्षीय सूरत राम मतदान करने पहुंचे। ग्राम पंचायत मझार के खलाशी-1 मतदान केंद्र में 81 वर्षीय शांति ठाकुर ने वोट डाला, जबकि ग्राम पंचायत घरनाणा में 80 वर्षीय भोम प्रकाश शर्मा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल के शालान वार्ड नम्बर-1 से 103 वर्षीय बुजुर्ग महिला पदमु देवी ने वोट डाला। कई बुजुर्ग सहारे के साथ मतदान केंद्रों तक पहुंचे। मतदान केंद्रों के बाहर लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते और उनका हौसला बढ़ाते दिखाई दिए। युवा मतदाताओं में भी चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिला। शिमला जिले की ग्राम पंचायत घरयाणा की 18 वर्षीय निकिता ने पहली बार मतदान किया। प्रदेशभर में हजारों नए मतदाता पहली बार पंचायत चुनाव का हिस्सा बन रहे हैं। सुबह के शुरुआती घंटों में ही कई क्षेत्रों में अच्छा मतदान दर्ज किया गया। शिमला जिला के विकासखंड रोहड़ू के 14 पंचायतों में सुबह नौ बजे तक 17.46 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया। वहीं दुरदराज डोडरा क्वार उपमंडल में सुबह नौ बजे तक 14.6 प्रतिशत मतदान हुआ। प्रशासन का कहना है कि जैसे-जैसे दिन चढ़ रहा है, वैसे-वैसे मतदान केंद्रों पर भीड़ बढ़ रही है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए प्रदेशभर में 16,539 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 3,554 मतदान केंद्र संवेदनशील और 1,585 अतिसंवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

भ्रष्ट अधिकारियों के आगे पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड हैं सुक्खू : जयराम

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने वर्तमान कार्यवाहक मुख्य सचिव को स्थायी नियुक्ति दिए जाने के फैसले की भी निंदा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस अधिकारी की नियुक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है और जहां कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। ऐसे संवेदनशील समय में उसी अधिकारी को स्थाई सीएस बनाना सरकार की नीयत पर बड़े सवाल खड़े करता है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री इतने बेबस हैं कि वह भ्रष्ट अधिकारियों को पुरस्कृत कर रहे हैं । उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति देने की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं उन्हीं

अधिकारियों से मुख्यमंत्री आज घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ, नेता प्रतिपक्ष ने जल सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब हर काम पूरा होने की गारंटी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के निलंबन पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी डायवर्ट करने के लिए 2,620 करोड़ रूपए की लागत से दो बड़ी टनल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में 2,352 करोड़ रूपए की लागत से 8.7 किलोमीटर लंबी चेनाब-ब्यास लिंक टनल बनाई जाएगी।

गुलमर्ग गोंडोला बचाव के बाद डीजीपी ने प्रशंसा पुरस्कारों की घोषणा की

श्रीनगर। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग गोंडोला सेवा में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के सफल अभियान में शामिल पुलिस और बचाव कर्मियों के लिए प्रशंसा पुरस्कारों की घोषणा की। पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य बचाव एजेंसियों के संयुक्त अभियान के बाद लगभग 320 पर्यटकों को बचाया गया। गुलमर्ग में बचाव टीमों को संबोधित करते हुए प्रभात ने कठिन मौसम और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कर्मियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चट्टानी इलाके, खराब मौसम और निलंबित केबल कारों से लोगों को निकालने की जटिलता सहित बड़ी चुनौतियों के बावजूद बचाव अभियान पूरा किया गया। डीजीपी ने पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी), जम्मू-कश्मीर सशस्त्र पुलिस और एसडीआरएफ के कर्मियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, ₹आज आप सभी ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को गौरवान्वित किया है।₹ प्रभात ने कहा कि ऑपरेशन में शामिल सभी कर्मियों को पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अभी तक डीजीपी कमेंडेशन डिस्क नहीं मिली है, उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा जबकि जिन कर्मियों को यह पहले ही मिल चुका है।

मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और संकल्प सिद्धि के प्रतीक : अनुराग ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि 26 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरूआत का प्रतीक बना। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, आकांक्षाओं और विकास यात्रा का उत्सव है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को धरातल पर उतारते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 12 वर्षों में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनकी दशकों से केवल कल्पना की जाती थी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद

370 और 35अ हटाकर देश को एक संविधान, एक निशान और एक विधान के सूत्र में पिरोने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जीएसटी के माध्यम से देश को एक राष्ट्र-एक बाजार की व्यवस्था मिली। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया है तथा रिकॉर्ड विदेशी निवेश आकर्षित किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसकी योजनाओं का सीधा लाभ गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग तक पहुंचा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर मिले, जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित की गई। उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों को धुएं से मुक्ति मिली, जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर भी अपनी नई पहचान स्थापित की है।

सेवानिवृत्ति से पहले संजय गुप्ता को सूक्खु सरकार का तोहफा, कार्यवाहक से बनाए गए नियमित मुख्य सचिव

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नियमित मुख्य सचिव किया है। खास बात यह है कि संजय गुप्ता अब तक कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे और 31 मई 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति भी तय है। ऐसे में रिटायरमेंट से महज पांच दिन पहले उन्हें कार्यवाहक से स्थायी मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रदेश सरकार की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल ने जनहित में संजय गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले वे अतिरिक्त मुख्य सचिव (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और हाउसिंग) के पद पर कार्यरत थे और साथ ही मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग

और हाउसिंग) का अतिरिक्त कार्यभार आईएएस अमरजीत सिंह सचिव सहकारिता को सौंपा गया है। सूक्खु सरकार ने अक्टूबर 2025 में संजय गुप्ता को कार्यवाहक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी थी। उस समय भी यह फैसला काफी चर्चा में रहा था। अब सरकार ने उनके अनुभव और प्रशासनिक कार्यशैली पर भरोसा जताते हुए उन्हें नियमित मुख्य सचिव बना दिया है। हालांकि उनका कार्यकाल केवल कुछ दिनों का ही बचा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार का यह फैसला कई मायनों में अहम माना जा रहा है। संजय गुप्ता को नियमित मुख्य सचिव बनाये जाने के बाद अब उन्हें छह माह का सेवा विस्तार मिलने की संभावना कम है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता लंबे समय से हिमाचल प्रशासन का अहम चेहरा रहे हैं। 5 जून 1966 को जन्मे संजय गुप्ता ने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। अपने करीब चार दशक लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों और पदों की जिम्मेदारी संभाली। वे प्रधान सचिव, सचिव, प्रबंध निदेशक, निदेशक, अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त उपायुक्त और उपमंडलाधिकारी जैसे पदों पर काम कर चुके हैं। प्रदेश में नए मुख्य सचिव को लेकर कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। 31 मई 2026 को उनकी सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के-के पंत (1993 बैच) को हिमाचल का अगला मुख्य सचिव बनाया जा सकता है, क्योंकि संजय गुप्ता के बाद वे सबसे वरिष्ठ आईएएस हैं।

शोपियां पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों पर पीआईटी-एनडीपीएस के तहत मामला किया दर्ज

शोपियां। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के अवैध व्यापार की रोकथाम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान दारमदोरा कीगाम के हिलाल अहमद भट विश्राम पाईन के मोहम्मद यूसुफ भट और पुडसू शोपियां के परवेज अहमद थोकर के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा कि शोपियां पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए डोजियर के बाद कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर द्वारा हिरासत के आदेश जारी किए गए थे जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी में उनकी कथित बार-बार संलिप्तता और उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर का हवाला दिया गया था। आरोपियों को क्रमश जम्मू की सेंट्रल जेल कोट भलवाल, जिला जेल राजौरी और जिला जेल पुंछ में रखा गया है। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवा कल्याण के लिए उनकी गतिविधियों से उत्पन्न गंभीर खतरा के कारण निवारक हिरासत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को दशार्ता है और जिले में मादक पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।

बसोहली में ईद-उल-अजहा की तैयारियां तेज स्वच्छता से लेकर सुरक्षा तक प्लान तैयार

एजेंसी (हि.स.)
बसोहली

ईद-उल-अजहा के अवसर पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए एडीसी बसोहली पंकज भगोत्रा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप-जिला स्तर पर त्योहार की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में तहसीलदार बसोहली सागर विश्वकर्मा, नगर समिति के कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार सहित स्वास्थ्य, जल शक्ति, बिजली, खाद्य एवं आपूर्ति, ग्रामीण विकास और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। एडीसी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से ईदगाहों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास साफ-सफाई और कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। जल शक्ति

विभाग को सभी धार्मिक स्थलों पर निर्बाध पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए, वहीं बिजली विभाग को त्योहार के दौरान लगातार बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने और आपात स्थिति से निपटने के लिए टीम तैयार रखने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को प्रमुख स्थानों पर मेडिकल टीम, दवाइयों और एंबुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग को प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए जबकि अग्निशमन विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया।

संक्षिप्त-समाचार

ऊना में आग का तांडव, प्रवासियों की 76 झुग्गियां राख

ऊना। ऊना मुख्यालय के साथ लगते बसाल गांव में प्रवासी मजदूरों की 76 झुग्गियां आग की भेंट चढ़ गई। आग से प्रवासी मजूदरों का घरेलू सामान, राशन, कपड़े, बिस्तर, बर्तन, नकदी जलकर राख हो गई। प्रारंभिक आंकलन में चार लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। अग्निशमन दलबल ऊना की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खड़पोश से बनी झुग्गियां राख में तब्दील हो चुकी थी। सूचना मिलते ही ऊना पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार ऊना-अंब नेशनल हाईवे पर बसाल पुल के सामने गत्ता उद्योग के साथ सटी प्रवासी मजदूरों की झुंगियों में मंगलवार दोपहर को आग लग गई। देखते ही देखते साथ-साथ सटी खड़पोश की झुंगियां आग की चपेट में आती गई। आग का भयावह रुप से दूर से ही दिख रहा था। इसी बीच सूचना मिलते ही अग्निशमन दलबल की टीम मौका पर पहुंची और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। जिस वक्त आग लगी, उस समय कई मजूदर दिहाड़ी मजदूरी पर गए हुए थे। जब उन्हें झुंगियों में आग लगने की सूचना मिली तो वह अपनी झुंगियों की तरफ दौड़े। घटनास्थल पर मजदूरों, महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गो की चीखों पुकार मची रही। लोग झुंगियों में अपना सामान खंगालते रहे, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी में वह असमर्थ रहे। बतां दे कि गर्मी का सीजन शुरू होते ही आग की घटनाओं में तेजी आई है। इससे ऊना मुख्यालय में पुराना होशियारपुर रोड़ पर लालसिंगी में दर्जनों झुंगियां आग से जल गई थी। जिसमें लाखों रुपयों का नुकसान हो गया था। वहीं अब बसाल में 76 झुंगियां जलने का मामला सामने आया है।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उधमपुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया

उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में वायु सेना रोड के करीब स्थित मियां बाग के पास धार रोड पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे सामान बेचने के लिए अवैध रूप से बनाए गए कई अस्थायी टिन शेड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार रौन मारूफ खान के अनुसार यह समस्या क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई थी और कई लोगों ने इसे लेकर तहसीलदार कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई थी। खान ने कहा कि यह मुद्दा काफी समय से चल रहा था। कई लोग डीसी कार्यालय और तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज करा रहे थे कि कई लोगों ने राज्य की जमीन पर अस्थायी शेड बना लिए हैं। यह एक राजमार्ग है और शाम को लोग यहां इकट्ठा होते हैं जिससे दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। क्षेत्र की संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकारी ने कहा कि कुल सात शेडों में से पांच को जनता ने स्वयं हटा दिया था इस बीच अन्य दो को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। हाल ही में वायु सेना और पुलिस के अनुरोध पर उन्होंने हमारे संज्ञान में लाया कि यहां के सात शेडों में से दो में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो सड़क पर फोकस करते हैं। यह एक संवेदनशील क्षेत्र है यहां एयरफोर्स स्टेशन हैं अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों की आवाजाही भी यहीं होती है। हमने उन अस्थायी शेडों को पहले ही नोटिस जारी कर आज हटा दिया है, पांच शेड खुद ही हटा दिए गए। हमने आज शेष दो शेड हटा दिए हैं।

अब नहीं मानेंगे आश्वासन, कठुआ में सफाई कर्मियों की सख्त चेतावनी के साथ हड़ताल शुरू

कठुआ। नगर परिषद कठुआ के अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मंगलवार से हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने नगर परिषद परिसर में एकत्र होकर लोकल बॉडी डायरेक्टर और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को उठाया। सफाई कर्मचारियों के प्रधान ने बताया कि उनकी स्थायीकरण की मांग वर्ष 2014 से लंबित है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कई चुनावों के दौरान उन्हें केवल आश्वासन ही मिला जबकि उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बार वे झूठे आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक उन्हें स्थायी नहीं किया जाता, हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों ने डेली वेजर्स को नियमित करने और सफाई कर्मचारियों की कमी को जल्द पूरा करने की भी मांग की। प्रधान ने बताया कि नगर परिषद में कुल 112 कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं जबकि 21 वार्डों के लिए पर्याप्त सफाई कर्मचारी नहीं हैं। इसके बावजूद शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि वे हड़ताल नहीं करना चाहते क्योंकि इससे शहर में गंदगी फैलती है लेकिन लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की है।

मंगलवार को लगातार चौथे दिन राजौरी के मांजकोट में आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी

राजौरी। सुरक्षाबलों द्वारा चलाया जा रहा व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) मंगलवार को लगातार चौथे दिन भी राजौरी जिले के मांजकोट सेक्टर के घने जंगलों में गंभीर मुगलन और दोरिमाल में जारी रहा। यह अभियान क्षेत्र में संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के बाद शुरू किया गया है। यह संयुक्त अभियान भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा पीर पंजाल क्षेत्र के दुर्गम वन क्षेत्र में चलाया जा रहा है।स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र में सुरक्षा तैनाती में काफी वृद्धि की गई है। स्थानीय निवासी आकिब खान ने कहा, संदिग्ध आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद से ही गंभीर मुगलन वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों की भारी मौजूदगी है। उन्होंने आगे कहा, पूरे क्षेत्र को कड़ी घेराबंदी में रखा गया है और तलाशी अभियान लगातार जारी है।

विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश डीसी कठुआ ने की प्रगति की समीक्षा

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने मंगलवार को जिला कैपेक्स बजट 2026-27, विधायक निधि और सांसद निधि के तहत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की।

बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जेपीडीसीएल सहित विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों का जायजा लिया गया। साथ ही डीडीसी, बीडीसी और पीआरआई ग्रांट्स के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति भी परखी गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके। उन्होंने ठेकेदारों के कार्यों की नियमित निगरानी और मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि एमएलए-सीडीएफ के तहत 748 कार्यों को मंजूरी मिली है जिनमें से 727 टेंडर, 713 आवंटित और 699 कार्य शुरू हो चुके हैं जबकि 542 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं एमपी लैड के तहत भी अधिकांश कार्यों में संतोषजनक प्रगति दर्ज की गई है। बैठक में एडीसी महिमा मदान, सीपीओ रणजीत ठाकुर, एसीडी अखिल सदोत्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मौसम — इस बार मनाली, शिमला से ज्यादा गर्म रहा

हिमाचल में फिर भीषण गर्मी, पारा 42 डिग्री पार

मैदानी जिलों में लू का 'येलो अलर्ट', सैलानियों के पसंदीदा हिल स्टेशनों पर गर्मी ने छुड़ाए पसीने

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में नौतपा के दूसरे दिन मंगलवार को भी सूरज के तेवर बेहद तीखे रहे और राज्य के कई इलाकों में भीषण गर्मी व लू ने लोगों को बेहाल किया। मैदानी और निचले इलाकों में गर्म हवाएं चलती रहीं, जबकि पहाड़ों में भी तपिश बढ़ गई।

प्रदेश का औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक दर्ज किया गया। हिल स्टेशन शिमला का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री ज्यादा रहा, जबकि मनाली में सामान्य से दो डिग्री अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। खास बात यह रही कि इस बार

मनाली, शिमला से ज्यादा गर्म रहा। मनाली में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में पारा 27 डिग्री रहा। हालांकि शिमला में सोमवार की तुलना में तापमान में करीब दो डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई। तेज धूप और बढ़ती गर्मी का असर पर्यटन स्थलों पर भी देखने को मिला। शिमला के रिज मैदान और मॉल रोड पर दोपहर के समय आम दिनों की तुलना में सैलानियों की आवाजाही कम रही। मनाली में भी दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। राज्य के निचले इलाकों में गर्मी का सबसे ज्यादा असर ऊना में देखने को मिला, जहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा हमीरपुर जिला के नेरी 39 डिग्री, सुंदरनगर 37.9, कांगड़ा 37.4, मंडी 37.4, सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन 36.7 और बिलासपुर के बरठीं 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुल्लू जिला के भुंतर में तापमान 34.5 डिग्री, सोलन में 34.5, चंबा में 32.3 और शिमला जिला के जुब्बड़हट्टी में 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी गर्मी महसूस की गई। किन्नौर जिला के कल्पा में 22.4, शिमला जिला के कुफरी-फागू में 22.7 और लाहौल स्पीति जिला के केलांग में 18.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार नौतपा के प्रभाव के चलते अगले एक दिन तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विभाग ने प्रदेश के आठ जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और चंबा में 27 मई को लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि इन इलाकों में अगले 24 घंटे तक गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई, लेकिन इससे तापमान पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। हालांकि 28 मई से मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 28 मई से प्रदेश में बादल बरस सकते हैं।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्कः 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति: अस्पताल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने, सख्त निगरानी और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का बड़ा फोकस

अस्पताल परियोजनाओं के लिए तय की गई सख्त समय-सीमा, थर्ड पार्टी क्वालिटी जांच और जवाबदेही व्यवस्था लागू

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने, निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। सरकार अब केवल औपचारिक समीक्षा तक सीमित न रहकर जवाबदेही आधारित कार्यप्रणाली के तहत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े बड़े निर्माण कार्यों हेतु 815 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में निर्धारित 210 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 288 प्रतिशत अधिक है। सरकार की कार्य निष्पादन आधारित सोच को दशार्ते हुए चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही 203.75 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को जारी कर दिए गए हैं, ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने स्वास्थ्य परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित विभागों को संशोधित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला नागरिक अस्पतालों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य भवनों, क्रिटिकल केयर ब्लॉकों, टीबी केंद्रों तथा विशेष आश्रय सुविधाओं से संबंधित

परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

सरकार ने लंबित परियोजनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को देरी के मामलों में जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कई प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के आदेश जारी किए गए।

अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में 100 से 200 बिस्तरों के विस्तार ब्लॉक के शेष कार्य को दोबारा आवंटित कर दिया गया है और इसका निर्माण फरवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं अस्पताल कर्मचारियों के आवासीय कार्यों को 30 मई 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भिवानी जिले के सिवानी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने तथा शेष कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

गुरुग्राम जिले में फरुखनगर उपमंडल अस्पताल के लंबित कार्यों को एक माह के भीतर पूरा कर स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार सेक्टर-10 गुरुग्राम स्थित नागरिक अस्पताल को 100 से 200 बिस्तरों तक अपग्रेड करने का कार्य मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा।

हिसार जिले के नारनौंद में 100 बिस्तरीय अस्पताल के ग्राउंड एवं प्रथम तल का कार्य 15 जून 2026 तक पूरा कर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पूरी परियोजना सितंबर 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। महेंद्रगढ़ जिले में 50 बिस्तरीय अस्पताल को 100 बिस्तरीय अस्पताल में विस्तारित करने की परियोजना की भी समीक्षा की गई तथा लंबित वित्तीय स्वीकृतियों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया।

पलवल जिले में सीएचसी हसनपुर और मंडकोला परियोजनाओं की नई समय-सीमा तय की गई है। वहीं रेवाड़ी जिले में पीएचसी अकेड़ा परियोजना में लागत वृद्धि और ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है।

सरकार ने एक बड़े सुधारात्मक कदम के तहत सभी नए स्वास्थ्य परियोजनाओं में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी (दअअ) और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से थर्ड पार्टी क्वालिटी जांच व्यवस्था लागू की है। अब स्वतंत्र ऑडिट और नियमित रिपोर्टिंग के माध्यम से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

स्वास्थ्य परियोजनाओं की बेहतर निगरानी और समन्वय के लिए सरकार ने एक समर्पित नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है।

बैठक में जिला अस्पतालों में मरीजों की सुविधाओं और सेवा गुणवत्ता सुधारने पर भी विशेष जोर दिया गया। सभी सीएमओ और पीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक 15 दिन में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट भेजें।

अस्पताल परिसरों की स्वच्छता, कार्यशील शौचालय, निर्बाध पेयजल आपूर्ति, एयर कंडीशनिंग सिस्टम तथा डीजी पावर बैकअप जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों में शामिल किया गया है। अस्पतालों में बार-बार महंगे बाथरूम फिटिंग चोरी होने की घटनाओं को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक टैप लगाने का निर्णय लिया गया है।

करनाल जिले में लंबित परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई तथा देरी के कारणों और सुधारात्मक कदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, वहां आवासीय क्वार्टरों के लिए अनुमान शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

नारनौल नागरिक अस्पताल को 100 से 200 बिस्तरों तक अपग्रेड करने की परियोजना में ठेकेदार विवादों के कारण रुके कार्यों पर भी सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। अधिकारियों को 15 से 20 दिनों के भीतर परिसर में पड़ी ठेकेदार की मशीनरी एवं सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा के दीर्घकालिक स्वास्थ्य विजन के तहत डॉ. सुमिता मिश्रा ने अस्पताल नियोजन, सिविल इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं के डिजाइन में विशेषज्ञ निजी सलाहकारों को आगामी परियोजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं, विशेषकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत बनने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए। इससे आधुनिक, तकनीक आधारित और मरीजों के अनुकूल स्वास्थ्य संस्थान विकसित किए जा सकेंगे।

सामाजिक संस्थाएं भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए तत्पर : एसीएस

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ

अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंदरू ने कहा कि हरियाणा सरकार की तर्ज पर स्वयंसेवी एवं सामाजिक संस्थाएं भी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कार्य कर रही हैं ताकि प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत कर सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन डॉ. राजा सेखर वुंदरू गुरु रविदास भवन सैक्टर 15 पंचकूला में अमर शहीद रामानन्द महाराज के 17वें शहीदी दिवस पर गुरु रविदास डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के शुभारंभ कार्यक्रम में संबोधित रहे थे। उन्होंने कहा कि सभा द्वारा लेबोरेटरी शुरू करना बड़ा ही सराहनीय कार्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं में शामिल हैं। यदि नागरिकों को उचित समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा मिल जाए तो वह समाज एवं देश विकसित देशों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधाओं के लिए डायलिसिस जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं भी सरकारी अस्पतालों में मुहैया करवाई जा रही हैं। विशेषकर बुजुर्गों एंव महिलाओं के लिए अलग से आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल विकसित किया जा रहा है जो बुजुर्गों के जीवन स्तर को सुधारने और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करवाने में कारगर साबित होगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की पारदर्शी निगरानी करना है। इसके अलावा हर जिला स्तर के अस्पताल में सभी प्रकार की जांच, अल्ट्रासाउण्ड एमआरआई जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कार्यक्रम के दौरान गुरु रविदास डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में उपयोग होने वाले केमिकल का एक साल का खर्च उठाने की भी घोषणा की। उन्होंने लेबोरेटरी में कार्यरत चिकित्सक एवं कर्मचारियों से विस्तार से जानकारी ली और गुरु रविदास महाराज के चरणों में मत्था टेका। इस अवसर पर नागरिकों के लिए दिनभर मेगा स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में मरीजों के ब्लड एवं पेशाब के नमूनों की जांच की गई। इसके अलावा चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परामर्श और आवश्यक दवाइयां भी वितरित की। समारोह के अध्यक्ष पूर्व चीफ इंजीनियर हरपाल सिंह ने सुपोत्र इधंत की स्मृति में चार लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च कर लेबोरेटरी संचालित करने में अहम भूमिका निभाई है।

सभा के प्रधान कृष्ण कुमार ने बताया कि लेबोरेटरी में आधुनिक स्तर की मशीनें लगाई हैं जिनमें हर प्रकार ब्लड एवं पेशाब के नमूनों की जांच की सुविधा सामान्य दर पर प्रदान की गई है। सभा की ओर से भविष्य में एमआरआई, अल्ट्रासाउंड आदि मशीनें भी लगाए जाने की योजना है ताकि रोगियों को अधिकांश स्वास्थ्य जांच सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाई जा सकें। इसके अलावा नशा जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए मुहिम चलाए जाने पर बल दिया।

मेधावी विद्यार्थियों की मार्कशीट केवल अंकों का कागज नहीं, माता-पिता के त्याग और शिक्षकों के मार्गदर्शन का है जीवंत प्रमाण: महीपाल ढांडा

- 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में बोले शिक्षा मंत्री
- असफल रहे छात्र निराश न हों, कमियों को पहचानकर दुगनी ताकत से उठ खड़े हों- श्री महीपाल ढांडा
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत गांव के आखिरी छोर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार का है लक्ष्य

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों की मार्कशीट केवल अंकों का एक कागज नहीं है। यह उनकी रातों की नींद, उनके माता-पिता के त्याग और शिक्षकों के निस्वार्थ मार्गदर्शन का जीवंत प्रमाण है। शिक्षा मंत्री आज पंचकूला के शिक्षा सदन में सरकारी स्कूलों के हरियाणा शिक्षा बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में 22 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को क्रमश 11 हजार, 8100 व 5100 रुपये से सम्मानित किया। समारोह में शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए केवल एक मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक अभिभावक के तौर पर बेहद गर्व और हर्ष का दिन है। आपकी इस शानदार सफलता पर पूरे हरियाणा को गर्व है। उन्होंने विद्यार्थियों की सफलता का एक बड़ा श्रेय उनके माता-पिता और गुरुजनों को देते हुए कहा कि जब बच्चे पढ़ाई के लिए जाग रहे थे, तब माता-पिता भी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ जाग रहे थे। श्री महीपाल ढांडा ने सरकार के संकल्प को दोहराते हुए साफ किया कि वर्तमान सरकार का एकमात्र लक्ष्य हरियाणा के हर बच्चे को वैश्विक स्तर की आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत प्रदेश के शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि गांव के आखिरी छोर पर रह रहे बच्चे को भी आगे बढ़ने के समान और बेहतर अवसर मिल सकें। हरियाणा के युवाओं में हुनर की कोई कमी नहीं है और सरकार का काम उनकी इसी ऊर्जा को सही दिशा देना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की यात्रा का एक पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं। आगे की राह में चुनौतियां और बड़ी होंगी, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि छात्रों का यही जज्बा उन्हें हर मोर्चे पर विजयी बनाएगा। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा का उपयोग केवल अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ही न करें, बल्कि इसका उपयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी करें, क्योंकि देश और प्रदेश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक अंक न ला पाने वाले विद्यार्थियों को निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परीक्षा के अंक आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। असफलता केवल यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। उन्होंने छात्रों को सीख दी कि वे अपनी कमियों को पहचानें और दुगनी ताकत से दोबारा उठ खड़े हों, आने वाला समय निश्चित रूप से उनका होगा।

महंगाई की मार से जनता त्रस्त: कुमारी सैलजा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सिरसा की सांसद, कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज देश की आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं की कमी से बुरी तरह परेशान है। पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों तथा रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार की नाकामी के कारण देश की जनता न केवल लंबी लाइनों में खड़ी रहने को मजबूर है, बल्कि महंगाई की दोहरी मार भी झेल रही है। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में भी सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं से आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने कहा कि सरकारी तेल कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं, जबकि आम जनता की जेब पर लगातार बोझ बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज उठाती रही है और आगे भी महंगाई, बेरोजगारी तथा जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। सांसद ने कहा कि दिसंबर 2023-24 तक पिछले 19 माह में क्रूड के दाम 29 प्रतिशत तक कम हुए है पर तेल के दाम कम नहीं किए गए। इस अवधि में कंपनियों ने 1.32 लाख करोड रुपये कमाए पर सरकार ने आम आदमी पर ध्यान देने के बजाए कंपनियों के हितों पर अधिक ध्यान दिया। जब क्रूड के दाम कम हो तो तेल के दाम भी घटाने चाहिए। सरकार को पारदर्शी मूल्य रखना चाहिए। कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से मांग की कि पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं के दाम तुरंत कम किए जाएं तथा जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए।

सीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता परेशानः सैलजा

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार की पेट्रोल-डीजल लूट के बाद अब सीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। सांसद ने कहा कि आज फिर सीएनजी के दामों में दो रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि पिछले 12 दिनों में सीएनजी के दामों में कुल छह रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है। सांसद ने कहा कि 15 मई को दो, 18 मई को एक, 23 मई को एक तथा 26 मई को फिर दो रुपये प्रति किलो की वृद्धि की गई है।

मेदांता अस्पताल के सहयोग से सुदृढ़ होंगी अटेली क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं : आरती सिंह राव

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने राज्य के ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, मेदांता फाउंडेशन के माध्यम से मेदांता अस्पताल के साथ एक समझौता ज्ञापन करने जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटेली और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फरुखनगर व मीरपुर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करना और उन्हें और अधिक मजबूत बनाना है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अनुसार, यह पूरी सहभागिता पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत संचालित की जाएगी। इस सहयोग के अंतर्गत प्रसूति कक्षों और सिजेरियन सेक्शन ओटी सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा। नवजात शिशुओं की देखभाल उन्नत डायग्नोस्टिक सेवाएं और एम्बुलेंस सहायता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा ,स्वास्थ्य कर्मचारियों की स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह समझौता ज्ञापन शुरूआत में तीन वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।

आरती सिंह राव ने उम्मीद जताई है कि इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद अटेली क्षेत्र में और इसके छह महीने के भीतर फरुखनगर और मीरपुर के सीएचसी में गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में बड़ा सुधार होगा। यह कदम राज्य के पिछड़े या कम सेवा वाले क्षेत्रों में माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

संक्षिप्त-समाचार

मंच 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की करेगा सुनवाई

चंडीगढ़ । उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता संतुष्टिह्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 27 मई 2026 को राजीव गांधी विद्युत भवन, पावर हाउस रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

अहिल्याबाई के नाम से जाना जाएगा सुपवा का गर्ल्स हॉस्टल

- महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए किया संघर्ष
- छात्राओं को मिलती रहेगी उनके नाम से प्रेरणा : कुलगुरु

सिटी दर्पण संवाददाता
रोहतक

दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (डीएलसीसुपवा) के गर्ल्स हॉस्टल को अब अहिल्याबाई होल्कर के नाम से जाना जाएगा। अहिल्याबाई ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। अब उनके नाम से हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को प्रेरणा मिलती रहेगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गर्ल्स हॉस्टल परिसर के मुख्य द्वार व हॉस्टल बिल्डिंग की एंट्री पर नया नाम लिखवा दिया है। रजिस्ट्रार डॉ गुंजन मलि क मनोचा के अनुसार कुलगुरु डॉ अमित आर्य की सोच थी कि गर्ल्स हॉस्टल का नामकरण किसी ऐसे महापुरुष के नाम पर किया जाए, जो शिक्षा के प्रति समर्पित रहा हो। जिसने अपने जीवन में आदर्श स्थापित किए हों। जिसके नाम से छात्राएं प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ऐसे में विभिन्न नाम पर विचार किया गया, जिसमें अहिल्याबाई होल्कर के योगदान को देखते हुए उनके नाम पर छात्रावास का नामकरण करने का फैसला लिया गया। डॉ मनोचा ने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन 4 फरवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। उसके बाद से अभी तक इसका नामकरण नहीं हुआ था। कुलगुरु डॉ अमित आर्य ने बताया कि अहिल्याबाई होल्कर (1725-1795) मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी रही। कम उम्र में पति के देहांत के बाद उन्होंने अपने राज्य की बागडोर संभाली और इंदौर को राजधानी बनाकर कुशल शासन किया। उन्होंने अपने शासन के दौरान न्यायप्रियता, प्रजा कल्याण व प्रशासनिक दक्षता के नए आयाम स्थापित किए। उनका जीवन त्याग, धर्म व जनसेवा के आदर्शों पर आधारित रहा।

आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार समय की आवश्यकता और जरूरत : सुमन शर्मा

- राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा प्रयोग संस्था के सौजन्य से मनीमाजरा में लगाया गया निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर
- चिकित्सा शिविर में 150 से ज्यादा लोगों ने करवाया स्वास्थ्य परीक्षण
- आयुर्वेद जीवन जीने की शैली, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक : डॉ. रितेश

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकूला द्वारा प्रयोग फाउंडेशन के सौजन्य से मनीमाजरा स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारा में निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ चंडीगढ़ नगर निगम की डिप्टी मेयर सुमन अमित शर्मा ने किया, जबकि विशिष्ट अतिथि हरियाणा नर्सिंग आफिसर वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष विनीता बांगड़ और मुख्य चिकित्सक के तौर पर डॉ. रितेश मौजूद रहीं। शिविर अध्यक्षता प्रयोग फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने की। कैंप में पहुंचने पर मुख्यातिथि डिप्टी मेयर सुमन शर्मा का डॉ. अनुराग कुशल, डॉ. मानसी ग्रेवाल और डॉ. रितेश ने पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया।

डिप्टी मेयर सुमन अमित शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार मौजूदा समय की आवश्यकता और जरूरत है। प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति में हर बीमारी का इलाज है। आयुर्वेद में हर रोग का इलाज प्रभावी ढंग है और आयुर्वेदिक दवाइयों का शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। आयुर्वेद इलाज के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है।

हरियाणा नर्सिंग आफिसर वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष विनीता बांगड़ ने कहा कि आयुर्वेद उपचार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। आयुष मंत्रालय द्वारा पंचकूला में राष्ट्रीय स्तरीय आयुर्वेद संस्थान की शुरूआत की गई है, जोकि आयुर्वेद के जरिये उपचार और प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभा रहा है।

प्रयोग फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि संस्था की शुरूआत जींद जिले में 2014 से हुई थी, जोकि सामाजिक कार्यों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। संस्था की ओर से डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप के साथ अब राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के साथ सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर की मुहिम शुरू की गई है। डॉ. रितेश ने कहा कि आयुर्वेद जीवन जीने की शैली है। आयुर्वेद उपचार पाचन तंत्र को मजबूत करने, तनाव कम करने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) संजीव शर्मा, डीन प्रोफेसर गुलाब चंद पमनानी तथा डीन इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व के नेतृत्व में निशुल्क चिकित्सा शिविरों के माध्यम से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

डॉ. अनुराग कुशल ने कहा कि पंचकर्म आयुर्वेद की एक प्राचीन एवं प्रभावी चिकित्सा पद्धति है, जो शरीर को भीतर से शुद्ध कर रोगों की जड़ पर कार्य करती है। उन्होंने बताया कि पंचकर्म के माध्यम से शरीर में जमा विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, जिससे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से लाभ मिलता है। डॉ. मानसी ग्रेवाल ने बताया कि उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गौरव गर्ग की मार्गदर्शन में 12 अति विशिष्ट ओपीडी संचालित हैं, हर रोज 500 से ज्यादा रोगी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं। आईपीडी में भी रोगियों को भर्ती कर उनका उपचार किया जाता है।

शिविर का आयोजन कैंप समन्वयक डॉ. अनुराग कुशल और डॉ. मानसी ग्रेवाल की देखरेख में हुआ, जिसमें पाचन संबंधी बीमारियों, चमड़ी रोग, जोड़ों का दर्द, हड्डियों से संबंधित बीमारियां, आंख, कान, नाक, शुगर, बीपी, बुखार, जुकाम, सर्वाइकल बीमारियों से संबंधित 150 से ज्यादा लोग पहुंचें, जिन्हें चिकित्सकों के परीक्षण के बाद निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर प्रयोग संस्था की बोर्ड मैंबर सीमा गुप्ता, चंडीगढ़ अध्यक्ष नितेश महाजन, हरप्रीत सिंह रेखी, मेडिकल आफिसर भवकीर्ति, डॉ. श्रेया, फार्मासिस्ट अर्शदीप कौर, नर्सिंग स्टाफ हिमांशु तथा एमटीएस अंशुल प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

संपादकीय

तृणमूल में भगदड़: टूटता संगठन, उठते सवाल

पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक नए और गंभीर मोड़ पर खड़ी है। सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के भीतर से जो संकट फूट पड़ा है, वह न केवल पार्टी के संगठनात्मक ढाँचे को हिला रहा है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने आप को एकजुट रख पाएगी। राज्य की कई नगरपालिकाओं में लगभग 101 पार्षदों के इस्तीफे और पार्टी से जुड़े 17 पार्षदों तथा स्थानीय नेताओं की हालिया हफ्तों में गिरफ्तारी – जिनमें जबरन वसूली से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप हैं – ने तृणमूल को उसके इतिहास के सबसे बड़े जमीनी संगठनात्मक संकट में धकेल दिया है। 25 मई को डायमंड हार्बर नगरपालिका से एक साथ आठ तृणमूल पार्षदों के इस्तीफे ने इस राजनीतिक भूकंप को और तीव्र कर दिया। यह इसलिए भी बेहद चिंताजनक है क्योंकि डायमंड हार्बर को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का सबसे मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है। किसी भी नेता के गृहक्षेत्र से विद्रोह की यह आवाज राजनीतिक दृष्टि से बेहद अपमानजनक और संगठनात्मक दृष्टि से खतरे की घंटी है। विभिन्न नगरपालिकाओं से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार नॉर्थ बैरकपुर से 15, गरुलिया से 18, कंटाई से 14, हालीशहर से 16 और भाटपाड़ा से 30 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। यह कोई एक जगह की नाराजगी नहीं, बल्कि पूरे राज्य में फैले असंतोष की एक समवेत अभिव्यक्ति है। जब किसी पार्टी के सौ से अधिक जनप्रतिनिधि एक साथ पद छोड़ दें, तो उसे केवल विपक्षी षड्यंत्र कहकर टाला नहीं जा सकता। इस्तीफों की यह लहर आंतरिक विद्रोह, स्थानीय नेताओं में गहरे असंतोष, गुटबाजी और तृणमूल-नियंत्रित नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार तथा सिंडिकेट राजनीति के खिलाफ जनाक्रोश की बढ़ती रिपोर्टों के बीच उठी है। वर्षों से बंगाल की नगरपालिकाएँ सेवा प्रदाता संस्थाओं से अधिक राजनीतिक दलों के स्थानीय अखाड़े बन गई थीं। ठेकेदारी, जमीन पर कब्जे और सिंडिकेट का जाल इतना गहरा था कि आम नागरिक की शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं था। निलंबित पूर्व तृणमूल प्रवक्ता रिजु दत्त ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि पार्टी 'ताश के पत्तों की तरह ढह' रही है। यह बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं, बल्कि खुद तृणमूल से जुड़े व्यक्ति का है। जब पार्टी के भीतर से ही ऐसी आवाजें आने लगें, तो नेतृत्व को आत्ममंथन करना ही होगा। संकट से घबराई ममता बनर्जी ने 22 मई को अपने कालीघाट आवास पर पार्षदों की बैठक बुलाकर उनसे सीधे कहा कि 'इस्तीफा मत दो – जिस क्षण इस्तीफा दोगे, वे झपट्टा मार लेंगे। जमीन पर टिके रहो और लोगों की सेवा करते रहो।' यह बयान जितना भावनात्मक था, उतना ही इस बात का स्वीकारोक्ति भी था कि पार्टी की जड़ें हिल रही हैं। इस पूरे संकट में एक और अध्याय जुड़ा जब तृणमूल सांसद काकोली घोष दस्तीदार की भाजपा सरकार की बैठक में उपस्थिति चर्चा का केंद्र बन गई। तृणमूल सांसद काकोली घोष दस्तीदार और दो अन्य विधायकों ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा बुलाई गई प्रशासनिक बैठक में भाग लिया। कोलकाता में आयोजित यह बैठक उत्तर 24 परगना और नदिया जिले के प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ थी, जो पश्चिम बंगाल के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक असामान्य दृश्य था। देगंगा से तृणमूल विधायक अनिसुर रहमान, स्वरूपनगर से विधायक वीना मंडल, हड्वा से विधायक अब्दुल मतीन सहित कुल छह अन्य विधायक भी इस बैठक में उपस्थित थे। गौरतलब है कि तृणमूल ने कभी भाजपा विधायकों को अपनी किसी प्रशासनिक बैठक में आमंत्रित नहीं किया था, इसलिए भाजपा का यह तृणमूल जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह घटना केवल एक बैठक में शामिल होने तक सीमित नहीं है। यह संकेत है कि तृणमूल के भीतर वे नेता जो अपनी बात मनवा नहीं पा रहे, जो पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं या जो अपने क्षेत्र में काम करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं – वे धीरे-धीरे दूसरे विकल्पों की तलाश करने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा एक दोहरी रणनीति अपना रही है – एक ओर उसकी सरकार अपनी कार्रवाइयों को कथित भ्रष्टाचार और सिंडिकेट से ग्रस्त नगरपालिकाओं की प्रशासनिक सफाई के रूप में प्रस्तुत कर रही है, और दूसरी ओर पार्षदों व अध्यक्षों पर बढ़ते दबाव ने उस स्थानीय राजनीतिक ढाँचे को अस्थिर करना शुरू कर दिया है जिसने एक दशक से अधिक समय से बंगाल के शहरी क्षेत्रों में तृणमूल को टिकाए रखा था। सिलीगुड़ी के वरिष्ठ पत्रकार प्रबीर प्रमाणिक के शब्दों में – 'बंगाल की नगरपालिकाएँ केवल नागरिक संस्थाएँ नहीं हैं। ये राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं।' यह कथन इस पूरी समस्या की जड़ को उजागर करता है। जब नगरपालिकाएँ जनसेवा के बजाय दलीय राजनीति का केंद्र बन जाती हैं, तो न केवल शासन व्यवस्था चरमराती है, बल्कि वहाँ काम करने वाले जनप्रतिनिधियों का भी मोहभंग होने लगता है। इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक नुकसान आम जनता का हो रहा है। कई नगरपालिकाएँ पहले से ही इसलिए सुचारु रूप से नहीं चल पा रहीं क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों ने नियमित रूप से कार्यालय आना बंद कर दिया है। जब पार्षद इस्तीफा देते हैं और कार्यालय सूने पड़ जाते हैं, तो पेयजल, सफाई, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएँ सबसे पहले प्रभावित होती हैं। राजनीतिक उठापटक में जो सबसे अधिक पिसता है, वह आम आदमी ही होता है। तृणमूल नेतृत्व को चाहिए कि वह इस संकट को केवल भाजपा की साजिश बताकर न टाले। अपने नेताओं की वैध शिकायतें सुनना, भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई करना और नगरपालिकाओं को वास्तविक सेवा संस्थाओं के रूप में पुनः स्थापित करना – यही वह रास्ता है जिससे पार्टी अपनी साख बचा सकती है। आत्मचिंतन के बिना केवल गिनती बचाने की राजनीति अधिक दिन नहीं टिकती।

अमेरिका-ईरान युद्ध से महंगाई के कारण आमजन प्रभावित

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (हि.स)

भले 1970 के तेल संकट जैसे हालात होने की आशंका न हो या 2008 जैसी वित्तीय मंदी के हालात भी न हो लेकिन एक बात साफ है कि अमेरिका-ईरान के बीच करीब तीन माह से चल रहे युद्ध के दुष्प्रभाव गहराने लगे हैं। चाहे एशिया के हों या यूरोपीय देश, सभी केवल वैश्विक तनाव ही नहीं अपितु ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने से बढ़ते दामों को रोकने में विफल रहे हैं। पिछले दस-पन्द्रह दिनों में ही हमारे देश में पेट्रोल-एलपीजी-सीएनजी- पीएनजी के दामों में एक बार नहीं अपितु तीन बार बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि वर्तमान हालात में सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विपक्ष चाहे लाख आरोप लगाये पर अंतरराष्ट्रीय हालात से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमजन से आग्रह को भी इसी संदर्भ में सकारात्मकता से लिया जाना चाहिए।

अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ईंधन संकट का बड़ा कारण अमेरिका-ईरान युद्ध न होकर इस युद्ध के कारण हार्मुज वैश्विक संकट बन गया है। हार्मुज के रास्ते से ही कच्चे तेल की आपूर्ति होती है और यहां तनाव के चलते हार्मुज जनडमरुमध्य रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। इससे आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यह तो वैकल्पिक उर्जा के रुप में देश में सोलर, विण्ड एनर्जी के क्षेत्र में पिछले सालों में योजनाबद्ध तरीके से तेजी से बेहतर काम हुआ है और इसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री इलेक्ट्रोनिक वाहनों के उपयोग या सोलर एनर्जी के उपयोग पर खुले तौर पर आग्रह करने की स्थिति में है। नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में देश में तेजी से काम हुआ है और हो रहा है जो एक हद तक संकट को कम करने में सहायक बन रहा है।

आज की दुनिया आइसोलेट दुनिया नहीं है। देशों की एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है। कहीं से ईंधन के लिए तो कहीं से खाद्यान्न, कहीं दवा, कहीं अन्य किसी वस्तु के लिए निर्भरता बढ़ी है। युद्ध के चलते इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सेवाएं प्रभावित हुई है। जहां तक देश की ही बात की जाए तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि की कीमत में बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ने लगा है। सीधी-सी बात है जब आवागमन महंगा होगा चाहे वह आम आदमी, सार्वजनिक क्षेत्र या लॉजिस्टिक का हो तो उसका सीधा वस्तुओं और सेवाओं पर पड़ेगा ही। यही कारण है ईंधन यानी तेल के भावों में बढ़ोतरी के साथ वस्तुओं और सेवाओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। इसके साथ ही आयात पर निर्भर वस्तुओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं।

जहां तक तेल का प्रश्न है, देश में खाद्य तेल और अखाद्य तेल दोनों प्रभावित हो रहे हैं। खाद्य तेलों में भी आयात पर निर्भरता अधिक है। लाख प्रयासों के बावजूद तिलहन मिशन से तिलहनों का उत्पादन तो बढ़ा है पर अभी विदेशी निर्भरता बनी हुई ही है। इसी तरह अन्य वस्तुओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। जहां तक सेवा क्षेत्र का प्रश्न है, स्वीगी-जोमेटो आदि सेवा प्रदाताओं ने पिछले दिनों अपने दामों में 16 फीसदी से भी अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने प्लानों को रिवाइज किया है तो उबेर-ओला जैसे सेवा प्रदाताओं ने किराया बढ़ा दिया है। साफ है कि लॉजिस्टिक लागत बढ़ेगी तो उसका असर सभी वस्तुओं में देखने को मिलेगा। भारत सरकार वेनेजुएला से वैकल्पिक तरीके से कच्चे तेल लाने का प्रयास कर रही है तो अन्य विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। लेकिन कच्चे तेल की आपूर्ति जब तक सामान्य नहीं हो जाती तब तक संकट पूरी तरह से समाप्त होने की कल्पना नहीं की जा सकती।

इन वैश्विक हालातों के पीछे अमेरिका-ईरान की हठधर्मिता ही है। अमेरिका-इजराइल ने ईरान से लड़ाई शुरू करते समय रूस-यूक्रेन युद्ध के हालातों से सबक नहीं लिया। रूस के सामने यूक्रेन जैसा देश होने के बावजूद आज तीन साल से भी अधिक समय होने के बावजूद निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंचा है। पर अमेरिका ने यह सोचा था कि दो-तीन दिन में ही ईरान को घुटने टिकवा देंगे और यही अमेरिका की नासमझी रही। मानो या न मानो पर वास्तविकता यह है कि आज अमेरिका के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने का संकट आ गया है और यही कारण है कि अंदरखाने अमेरिका और ट्रंप किसी भी तरह से सीजफायर के लिए प्रयासरत है।

इसमें दो राय नहीं कि युद्ध में नुकसान अमेरिका को अधिक हो रहा है। ईरान तो अपने घर से लड़ रहा है और उसके निशाने पर आसपास के देश हैं। ऐसे में स्टेक अमेरिका-इजराइल का ही हो जाता है। इसके अलावा एक बात और समझनी होगी कि ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में आये दिन तुगलकी फरमान जारी कर दुश्मन ही दुश्मन बनाए हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने अमेरिका के ही अधिकांश लोगों का भरोसा खो दिया है। ऐसे में सम्मानजनक सीजफायर ही अमेरिका के लिए इस संकट से निकलने का रास्ता रह गया है और इसके लिए ही अंदरखाने प्रयास जारी है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेष: आज आपको किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। व्यापार में अपेक्षित लाभ मिलने से संतोष रहेगा। हालांकि परिवार में झिझक के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: राजनीति से जुड़े लोगों को आज मजबूत जनसमर्थन मिल सकता है। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। परिवार के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और आप अपनों के साथ खुशहाल समय बिताएंगे। घर में मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम हो सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: आज आत्मविश्वास में कुछ कमी महसूस हो सकती है। अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचें। गलत फैसलों के कारण रिश्तों में दूरी आ सकती है। विवादों को बातचीत से सुलझाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बेवजह की बहसों में समय न गंवाएं, इससे नुकसान हो सकता है। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। कारोबार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। नई योजनाओं की शुरूआत के लिए दिन अनुकूल है। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा के योग भी बन सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: करियर को लेकर मन थोड़ा असंतुष्ट रह सकता है। किसी को उधार देने से बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। पढ़ाई और ज्ञान से जुड़ी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। बिना पूरी जानकारी के किसी बात पर प्रतिक्रिया न दें। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: दाम्पत्य जीवन में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। व्यापार विस्तार के लिए दिन अच्छा है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में हल्की परेशानियां आ सकती हैं। परिवार से जुड़े विवादों को सुलझाने का सही समय है। *(सिटी दर्पण)*

तुला: जीवनसाथी की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। हृदय संबंधी रोगियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शुभचिंतकों की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: आज आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। घर में धार्मिक माहौल रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। रिश्तेदारों से सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बच्चों के साथ व्यवहार मधुर रखें। *(सिटी दर्पण)*

धनु: आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे। लंबे समय से अटके काम पूरे होने से खुशी मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपकी प्रबंधन क्षमता की सराहना होगी। दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें। *(सिटी दर्पण)*

मकर: जीवनसाथी को आप पर गर्व महसूस होगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाने का कार्यक्रम बन सकता है। अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालने से बचें। कार्यक्षेत्र में आ रही परेशानियां दूर होंगी। विद्वानों और अनुभवी लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: आज आमदनी में कमी आ सकती है और काम में बाधाएं आ सकती हैं। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। कुछ कड़वे अनुभव मिल सकते हैं। अहंकार के कारण रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अपने मन की हर बात दोस्तों से साझा करने से बचें। *(सिटी दर्पण)*

मीन: आज आपके फैसलों की सराहना होगी। विवाह से जुड़ी अड़चनें दूर हो सकती हैं। समाज में सम्मान बढ़ेगा। प्रेमी युगल के लिए दिन खास रहेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे और घर के लिए खरीदारी भी कर सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

एआई का जनजातीय भाषाओं में संवाद: समावेशी विकास का द्योतक

रंजना चोपड़ा

हमारे देश भर में फैले जंगलों, पहाड़ियों और दूरदराज की बस्तियों में, एक शांत लेकिन सफल परिवर्तन चल रहा है। जनजातीय समुदाय लंबे समय से भारत की विकास गाथा के केंद्र में अपने उचित स्थान का इंतजार कर रहे थे। आज वे राष्ट्र की प्रगति के सक्रिय वास्तुकार के रूप में उभर रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव की यही भावना है: विकसित भारत की यात्रा का एक राष्ट्रीय उत्सव, जहां प्रगति भूगोल या परिस्थिति का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का समान रूप से अधिकार है।

महत्वाकांक्षा का पैमाना

यह समझने के लिए कि प्रौद्योगिकी जनजातीय विकास के लिए अपरिहार्य क्यों हो गई है, किसी को पहले चुनौती की व्यापकता को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए), राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और संबंधित पहलों में 549 जिलों और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,911 ब्लॉकों के 63,000 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 5.5 करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिक लाभान्वित हुए हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) पर विशेष ध्यान देने के साथ, इन प्रयासों का उद्देश्य आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसी आवश्यक सेवाओं का सम्पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है। इस तरह के विविध और विस्तृत इलाके में हर परिवार तक पहुंचने के लिए ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है जो डेटा-संचालित, कनेक्टेड और उत्तरदायी होती है और यही हम तैयार कर रहे हैं।

इस वर्ष जनजातीय गरिमा उत्सव का आयोजन लगभग चार विषयगत सप्ताह के आसपास किया जा रहा है, जो एक साथ जनजातीय विकास के पूर्ण आयाम को दशार्ते हैं। उद्घाटन का विषय, 'विकास के एक वाहक के रूप में प्रौद्योगिकी', इस बात को दशार्ता है कि कैसे डिजिटल सिस्टम, विज्ञान और नवाचार भारत के कुछ दूरस्थ समुदायों तक शासन और अवसर का विस्तार करने में मदद कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण के केंद्र में एक सरल सिद्धांत निहित है: जनजातीय भाषाओं, संस्कृतियों, विरासत और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का पर्याप्त सम्मान करते हुए विकास को अंतिम दूरी तक पहुंचना चाहिए।

प्रौद्योगिकी द्वारा जनजातीय गरिमा को बढ़ावा

उद्देश्य के साथ निर्देशित होने पर प्रौद्योगिकी क्या हासिल कर सकती है, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बिरसा 101 यानी सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी सीआरआईएसपीआर-आधारित जीन थेरेपी है। सिकल सेल रोग लंबे समय से जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य की एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है और भारत अब समानता और पहुंच में निहित उन्नत विज्ञान के साथ उस चुनौती का जवाब दे रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी) और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अनुसंधान, नैदानिक परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। सीएसआईआर-आईजीआईबी में हाल ही में एक संगोष्ठी में वैज्ञानिकों, नीति निमार्ताओं और सिकल सेल योद्धाओं को एक साथ लाया गया, जो वैज्ञानिक प्रगति और प्रयासों के पीछे की मानवीय तात्कालिकता दोनों को दशार्ता है।

साझा लक्ष्य स्पष्ट है: एक किफायती, एकमुश्त उपचारात्मक उपचार विकसित करना जो जरूरतमंद हर आदिवासी परिवार तक पहुंच सके। बीआईआरएसए 101 केवल चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि से भी बढ़कर है। यह एक घोषणा है कि भारत का सबसे उन्नत विज्ञान अपने सबसे पात्र समुदायों की सेवा करेगा।

यह दृढ़ विश्वास एक पहल से कहीं अधिक गहरा है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) और आयुजेनोमिक्स जैसे प्रयास दशार्ते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक आदिवासी समुदायों द्वारा लंबे समय से संरक्षित समृद्ध औषधीय और पारिस्थितिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण, मान्यीकरण और संरक्षण में मदद कर सकती है।

समावेशन की यही भावना इस बात को आकार दे रही है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जनजातीय विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में, मंत्रालय ने एक सरल लेकिन दृढ विश्वास पर आधारित एआई-सक्षम प्लेटफार्मों की श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भाषा एक बाधा नहीं है जिसे दूर किया जाना है, बल्कि एक पहचान है जिसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। आदि वाणी, जनजातीय भाषाओं के लिए एआई-संचालित अनुवादक, टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच अनुवाद, ओसीआर और आदिवासी भाषाओं में सरकारी योजना की जानकारी के वितरण का समर्थन करता है, जिससे नागरिकों को घर पर बोलने वाली भाषा में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ने में सक्षम बनाया जाता है। ट्राइबॉट एक बहुभाषी संवादी एआई सहायक है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को तत्क्षण मार्गदर्शन और शिकायत निपटारे में सहायता प्रदान करके इस प्रयास को और मजबूत करता है। भगवान बिरसा मुंडा सेल और आईआईटी दिल्ली के साथ आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान भी इन प्रयासों पर चर्चा की गई, जो जनजातीय भाषाओं के दीर्घकालिक संरक्षण और सुदृढ़ीकरण सहित एआई के सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और समुदाय-केंद्रित इस्तेमाल पर केंद्रित थी।

प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक अभिकथन और आर्थिक सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन रही है। आगामी ट्राइबएक्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जनजातीय कलाओं, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान, संगीत, शिल्प और सांस्कृतिक अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। इस प्रयास को पूरा करते हुए, जनजातीय भारत का प्रस्तावित जीआई संभावित कला और शिल्प एटलस भौगोलिक संकेत क्षमता के साथ जनजातीय हस्तशिल्प, वन उत्पादों और पारंपरिक कला रूपों का डिजिटल रूप से मानचित्रण करेगा, जिससे ब्रांडिंग, बाजार पहुंच और जनजातीय बौद्धिक विरासत की पहचान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पायलट आधार पर पांच राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में इनोवेशन हब की योजना बनाई गई है, जो नवाचार के नेतृत्व वाले आदिवासी उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए डिजाइन और उत्पाद विकास सहायता, जीआईएस-आधारित योजना डैशबोर्ड और इनक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर और आगे बढ़ेंगे।

प्रौद्योगिकी जनजातीय समुदायों तक शासन के तरीके को समान रूप से बदल रही है। पीवीटीजी घरेलू सर्वेक्षणों के लिए पीएम-जनमन के तहत सर्वेक्षण सेतु दूरदराज के क्षेत्रों में कल्याण वितरण की तत्क्षण, जियो-टैग निगरानी को सक्षम बनाता है। 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में संचालित, इस प्लेटफॉर्म ने 8,552 सर्वेक्षणकताओं के समर्थन के साथ पहले ही 3.43 लाख घरेलू प्रस्तुतियां दर्ज की हैं। इस तरह की डेटा-संचालित प्रणालियां यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि प्रत्येक पात्र परिवार की पहचान की जाए और उसे आवश्यक सेवाओं से जोड़ा जाए। इसके साथ ही मंत्रालय दावा प्रस्तुतीकरण, जीआईएस-आधारित मानचित्रण, वर्कफ्लो की निगरानी और शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एआई-सक्षम वन अधिकार अधिनियम शासन मंच विकसित कर रहा है। साथ में, ये पहल आदिवासी नागरिकों के लिए शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और सुलभ बना रही हैं।

जनजातीय समुदाय: विकसित भारत के वाहक

एक क्षण ऐसा होता है, जो उस सार को पकड़ लेता है, जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। यह किसी नीतिगत दस्तावेज या मंत्रिस्तरीय समीक्षा में नहीं पाया जाता है। यह तब पाया जाता है जब दूरदराज की बस्ती की एक आदिवासी महिला, तकनीक से, भाषा से सशक्त होती है और उसे इस बात का अहसास होता हो कि उसकी बात को राष्ट्र सुन रहा है। ऐसे में वह अपनी शर्तों पर सरकारी सेवाओं से जुड़ती है और पूरी गरिमा के साथ जवाब प्राप्त करती है। वह क्षण किसी यात्रा का अंत नहीं है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा में एक नए अध्याय की शुरूआत है।

जनजातीय गरिमा उत्सव इस संदेश को गर्व के साथ ले जाता है। जनजातीय समुदाय, अपनी दृढता, अपने पारिस्थितिक ज्ञान, अपनी कलात्मक परंपराओं और इस भूमि में अपनी गहरी जड़ों के साथ, विकसित भारत की दहलीज पर इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इसके सबसे शक्तिशाली और प्रेरक वाहकों में शामिल हैं। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी दूरियों को पाटती है, जैसे-जैसे विज्ञान उपचार प्रदान करता है, जैसा कि एआई जंगलों और पहाड़ियों की भाषाओं में बोलता है, और जैसे-जैसे शासन सबसे दूर के गांव के अंतिम परिवार तक पहुंचता है, हम हर दिन भारत के करीब आते हैं जो न केवल व्यापकता के रूप में विकसित है, बल्कि अपनी मानवता में परिपूर्ण है। यह वह विकसित भारत है जिसे हम माननीय प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर एक साथ मिलकर निर्मित कर रहे हैं।

(लेखिका भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव हैं)

जब मैदान जागे, नशे भागे

जतिंदर पाल मल्होत्रा

ऐसे समय में जब समाज का युवा वर्ग भ्रम, अवसाद, चिंता, अकेलेपन और नशे जैसी भयावह समस्याओं से जूझ रहा है, खेल, शारीरिक फिटनेस और योग के माध्यम से एक मौन क्रांति जन्म ले रही है। 12 विभिन्न खेलों में लगभग 3000 विद्यार्थियों की भागीदारी वाला यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन, एक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है।

दशकों तक भारत में अनेक सरकारों ने खेलों को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता के बजाय केवल एक अतिरिक्त गतिविधि के रूप में देखा। खेल अवसंरचना की उपेक्षा हुई, मैदान कंक्रीट के जंगलों में बदल गए और शारीरिक शिक्षा को रटने वाली पढ़ाई के पीछे छोड़ दिया गया। इस उपेक्षा के परिणाम आज स्पष्ट दिखाई देते हैं– विद्यार्थियों में बढ़ता तनाव, स्क्रीन की लत, सामाजिक संबंधों का कमजोर होना, मानसिक विकारों में वृद्धि और विशेष रूप से पंजाब जैसे क्षेत्रों में युवाओं के बीच नशे का भयावह प्रसार।

जिस युवा के जीवन में उद्देश्य नहीं होता, वह आसानी से भटक जाता है। जिस शरीर में अनुशासन नहीं होता, वह कमजोर हो जाता है। और जिस पीढ़ी के पास दिशा नहीं होती, वह नशे और निराशा का आसान शिकार बन जाती है। यही वह स्थान है जहाँ खेल केवल खेल नहीं रह जाते।

ऐसी खेल पहलों का महत्व केवल पदक या ट्रॉफियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे बच्चों के भीतर एक मजबूत मनोवैज्ञानिक संरचना तैयार करती हैं। जब कोई विद्यार्थी हर सुबह अभ्यास करने, स्वयं को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धा करने और अपने से बड़े किसी उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने के संकल्प के साथ उठता है, तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से दृढ़ता, अनुशासन और आत्मसम्मान विकसित होता है। फुटबॉल का मैदान, कुश्ती का अखाड़ा, बैडमिंटन कोर्ट या एथलेटिक्स ट्रैक अक्सर वह पहला विद्यालय बन जाते हैं जहाँ धैर्य, नेतृत्व, टीम भावना और भावनात्मक नियंत्रण वास्तव में सीखा जाता है। पंजाब के संदर्भ में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

पंजाब ऐतिहासिक रूप से वीरों, खिलाड़ियों और अद्वितीय साहस की भूमि रहा है। हॉकी के महान खिलाड़ियों से लेकर ओलंपिक विजेताओं तक, कबड्डी के मैदानों से लेकर सैन्य बटालियनों तक– शारीरिक शक्ति और अनुशासन इसकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में नशे ने इसी ऊर्जा और जज्बे को निशाना बनाने की कोशिश की। नशा केवल शरीर को नष्ट नहीं करता, वह महत्वाकांक्षा को समाप्त कर देता है।

जो युवा खेलों से जुड़ा होता है, वह कृत्रिम नशे की तलाश कम करता है, क्योंकि प्रतियोगिता स्वयं उसे स्वाभाविक आनंद, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुष्टि देती है। साथियों की सराहना, स्वयं में सुधार का गर्व, जीत का उत्साह और हार से मिलने वाले सबक– ये सब मिलकर एक सकारात्मक भावनात्मक वातावरण बनाते हैं। यही कारण है कि आज खेल मनोविज्ञान को विश्वभर में नशे के खिलाफ सबसे प्रभावशाली हथियारों में से एक माना जाता है।

शारीरिक फिटनेस मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है, जिसे समाज अक्सर कम आंकता है। व्यायाम मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाता है, मनोदशा को स्थिर करता है, एकाग्रता को बेहतर बनाता है और चिंता व आक्रामकता को कम करता है। भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़ा योग इस प्रक्रिया को आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। जहाँ खेल शरीर को ऊर्जा देते हैं, वहीं योग मन को स्थिर करता है। दोनों मिलकर ऐसी पीढ़ी तैयार करते हैं जो केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो।

आधुनिक शोध लगातार यह सिद्ध कर रहे हैं कि नियमित शारीरिक गतिविधियाँ ध्यान संबंधी विकारों, तनाव, भावनात्मक अस्थिरता और सामाजिक अलगाव से जूझ रहे बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। अउऌऊजैसे विकारों को भी खेलों के माध्यम से बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि खेल अतिरिक्त ऊर्जा को अनुशासन, दिनचर्या और उत्पादकता में बदल देते हैं। लेकिन शायद खेलों का सबसे बड़ा योगदान 'अपनापन' है।

आज का युवा डिजिटल अकेलेपन के युग में जी रहा है। सोशल मीडिया पर हजारों 'दोस्त' भी उस भावनात्मक जुड़ाव की जगह नहीं ले सकते जो मैदान में साथ खेलने से बनता है। जो बच्चा किसी टीम का हिस्सा बनता है, उसके भीतर आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान विकसित होती है। खेल का मैदान वह स्थान बन जाता है जहाँ जाति, भाषा, धर्म और आर्थिक स्थिति का महत्व समाप्त हो जाता है। क्रिकेट की गेंद यह नहीं पूछती कि आप कौन हैं; वह केवल यह पूछती है कि क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं। यही भारत की वास्तविक भावना है।

चंडीगढ़ भाजपा द्वारा आयोजित यह बहु-खेल प्रतियोगिता राष्ट्रीय एकता का भी एक महत्वपूर्ण मंच बनती है। विभिन्न स्कूलों, समुदायों और संस्कृतियों से आए विद्यार्थी एक साथ खेलते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, सीखते हैं और उत्सव मनाते हैं। ऐसी पहलें सामाजिक समरसता को मजबूत करती हैं और युवाओं के भीतर अलगाव की भावना को कम करती हैं।

खेल आशा भी देते हैं। हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी या राजनेता नहीं बनेगा, लेकिन हर बच्चे को जीवन में एक उद्देश्य मिलना चाहिए। खेल वही उद्देश्य प्रदान करते हैं। वे सिखाते हैं कि सफलता विरासत में नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास और अनुशासन से अर्जित होती है। जो विद्यार्थी पेशेवर खिलाड़ी नहीं भी बनते, वे भी आत्मविश्वास, फिटनेस, टीमवर्क और संघर्षशीलता जैसे गुण अपने जीवन के हर क्षेत्र में लेकर जाते हैं।

इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। खेलों से जुड़ा विद्यार्थी विनाशकारी आदतों से दूर रहने की अधिक संभावना रखता है, क्योंकि उसके पास बचाने के लिए बहुत कुछ होता है– उसकी क्षमता, प्रतिष्ठा, सपने और पहचान। एक खिलाड़ी त्याग करना सीखता है। वह समझता है कि क्षणिक सुख अक्सर दीर्घकालिक लक्ष्यों को नष्ट कर देते हैं। यही समझ नशे, अवसाद और नकारात्मकता के विरुद्ध एक ढाल बन जाती है।

समाज और अभिभावकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक शारीरिक गतिविधियों को पढ़ाई में बाधा माना गया, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। स्वस्थ शरीर मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाता है, एकाग्रता को मजबूत करता है और शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। दुनिया की अग्रणी संस्थाएँ आज समग्र विकास पर बल दे रही हैं, क्योंकि केवल बौद्धिक विकास बिना मानसिक और शारीरिक संतुलन के अधूरा होता है। भारत आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। विकसित भारत की ओर बढ़ते इस राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल तकनीक या अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि उसके युवाओं की गुणवत्ता, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य से तय होगी।

और स्वस्थ युवा केवल बंद कमरों में तैयार नहीं होते।
वे खेल के मैदानों में बनते हैं।
वे अनुशासन से आकार लेते हैं।
वे योग से संतुलित होते हैं।
वे प्रतियोगिता से प्रेरित होते हैं।
और वे उद्देश्य से सुरक्षित रहते हैं।

इसीलिए चंडीगढ़ भाजपा की यह पहल केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जो दिखाता है कि खेल किस प्रकार नशे, निराशा और मानसिक पतन के विरुद्ध सामाजिक क्रांति बन सकते हैं। हर नया स्टेडियम, हर प्रतियोगिता, हर योग सत्र और फिटनेस की ओर बढ़ाया गया हर कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक समरसता और मानवीय उत्कृष्टता में निवेश है।

क्योंकि जब कोई बच्चा रैकेट उठाता है, फुटबॉल को छूता है, हॉकी स्टिक पकड़ता है या योग मैट पर कदम रखता है, तब वह केवल एक गतिविधि नहीं चुन रहा होता।

वह विनाश के ऊपर जीवन को चुन रहा होता है।
वह नशे के ऊपर उद्देश्य को चुन रहा होता है।
वह अराजकता के ऊपर अनुशासन को चुन रहा होता है।
और वह अंधकार के ऊपर आशा को चुन रहा होता है।

लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही ने पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम ने 26 मई 2026 को चंडीमंदिर सैन्य स्टेशन में मुख्यालय पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम का स्थान लिया है, जिन्होंने सेना मुख्यालय में महानिदेशक रणनीतिक योजना (डायरेक्टर जनरल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग) का पदभार संभालने हेतु कार्यभार ग्रहण किया है।

पंजाब पब्लिक स्कूल, नाभा और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल साही को दिसंबर 1988 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ था और वर्तमान में वे राजपूत रेजिमेंट के कर्नल के प्रतिष्ठित पद पर आसीन हैं। जनरल अधिकारी को उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों सहित सियाचिन ग्लेशियर में व्यापक परिचालन अनुभव प्राप्त है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) तथा काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स (किलो) में अपनी बटालियन और एक इन्फैंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। उन्हें भारतीय सेना की सबसे बड़ी कोर, 3 कोर, की कमान संभालने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्वी सीमाओं, भारत-म्यांमार सीमा तथा उत्तर-पूर्व के छह राज्यों के आंतरिक क्षेत्रों तक फैली हुई है। मई 2023 में मणिपुर में हुए जातीय संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में आधारभूत संरचना के उन्नयन और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नियुक्ति से पूर्व वे आर्मी वॉर कॉलेज, महू के कमांडेंट के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने पेशेवर सैन्य शिक्षा को उभरती परिचालन आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुरूप बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कीं। उनके नेतृत्व में संस्थान को 15 जनवरी 2026 को प्रतिष्ठित ह्लचीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यूनिट अप्रिसिएशनह्व से सम्मानित किया गया।

जनरल अधिकारी ने कई महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों पर भी कार्य किया है, जिनमें एक ऑपरेशनल कोर के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ, अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य संचालन तथा सेना मुख्यालय में महानिदेशक सूचना युद्ध (इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर) शामिल हैं।

उन्होंने सभी महत्वपूर्ण पेशेवर पाठ्यक्रम पूरे किए हैं, जिनमें डीएसएससी वेलिंगटन का स्टाफ कोर्स, आर्मी वॉर कॉलेज महू का हायर कमांड कोर्स तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली का एनडीसी कोर्स शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल साही के पास दो एमफिल डिग्रियाँ तथा रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर डिग्री है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल तथा सेना मेडल से सम्मानित किया गया है।

पदभार ग्रहण करने के उपरांत लेफ्टिनेंट जनरल साही ने वीर स्मृति युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिचालन तत्परता, क्षमता विकास तथा सभी रैंकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

केंद्र की 2,620 करोड़ की जल परियोजना से पंजाब को नई उम्मीद: विक्रमजीत साहनी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

राज्यसभा सांसद एवं पद्मश्री डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने भारत सरकार द्वारा भारत के अधिकार वाले सिंधु बेसिन के जल के अधिकतम उपयोग हेतु चिनाबझ्रब्यास लिंक सुरंग एवं संबद्ध परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत सरकार का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया है। डॉ. साहनी ने कहा कि प्रस्तावित 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से चिनाब नदी के अतिरिक्त जल को ब्यास बेसिन में मोड़ा जा सकेगा। यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम है, जिससे पंजाब को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय राष्ट्रीय जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पंजाब के समक्ष बढ़ती जल चुनौतियों के समाधान के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाब के गंभीर जल संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. साहनी ने कहा कि वे लगातार पंजाब के नदी जल को अन्य राज्यों की ओर मोड़े जाने का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब अपने वार्षिक पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधनों का लगभग 164 प्रतिशत दोहन कर रहा है तथा राज्य के 23 में से 19 जिले भूजल के अत्यधिक दोहन की श्रेणी में आ चुके हैं। डॉ. साहनी ने कहा कि चिनाब, झेलम एवं सिंधु नदी प्रणालियों के अतिरिक्त जल को पंजाब की ओर मोड़ने से भूजल पुनर्भरण, कृषि तथा दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल पंजाब के किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने, गिरते भूजल स्तर को रोकने तथा राज्य को मरुस्थलीकरण के बढ़ते खतरे से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक समृद्ध, सुरक्षित और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी।

वड़िंग ने फर्जी ऑडियो वायरल करने के खिलाफ डीजीपी और एसईसी को की शिकायत

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब पुलिस के महानिदेशक और राज्य चुनाव आयोग को शिकायत भेजकर उनके नाम से जोड़ी जा रही एक फर्जी ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में, डीजीपी और राज्य चुनाव आयोग को भेजी गई अलग-अलग शिकायतों में वड़िंग ने कहा है कि यह एक फर्जी ऑडियो क्लिप है, जिसे सात वर्ष पहले भी उनकी छवि खराब करने और बदनाम करने के लिए फैलाया गया था। अब स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान इसे फिर से जानबूझकर वायरल किया जा रहा है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब राज्य एस.सी कमिशन के चेयरमैन ने इस क्लिप की सत्यता या फर्जी होने की जांच किए बिना ही इसका सुओ मोटो नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि चुनावों के दौरान इस क्लिप को फैलाने के पीछे एक सुनियोजित साजिश है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने डीजीपी और राज्य चुनाव आयोग, दोनों से अपील की कि वे इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लें और संबंधित अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कर दोषियों की पहचान करने के निर्देश दें। वड़िंग ने कहा कि आज या कल, आखिरकार हम मेरे खिलाफ चलाए जा रहे इस दुष्प्रचार अभियान के पीछे शामिल लोगों की पहचान कर लेंगे और कानून के अनुसार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

जमीन पर काम करके पंजाब सरकार ने पूरे किए वादे : भगवंत मान

यज्ञांश शर्मा
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने केवल प्रचार के लिए घोषणाएं करने के बजाय पंजाब के लोगों को जमीनी स्तर पर वास्तविक परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित किया है। एनडीटीवी नवा पंजाब समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। भगवंत मान ने कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने लोगों से किए गए कई वादों को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत घरों को शून्य बिजली बिल मिल रहे हैं, जिससे बढ़ते खर्चों से जूझ रहे आम परिवारों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने बिना

किसी भ्रष्टाचार और राजनीतिक सिफारिश के पारदर्शी तरीके से 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं।

उन्होंने कहा कि अब योग्य युवाओं को केवल मेरिट के आधार पर रोजगार मिल रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास पर बोलते हुए भगवंत मान ने कहा कि राज्यभर में 44,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और सकारात्मक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार लगभग 3,000 खेल मैदान और स्टेडियम विकसित कर रही है। औद्योगिक विकास पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी प्रशासन, उद्योग हितैषी नीतियों और बेहतर बिजली प्रबंधन के कारण पंजाब में निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लुधियाना और मंडी गोबिंदगढ़ जैसे औद्योगिक केंद्रों में दोबारा विकास की रफ्तार दिखाई दे रही है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य ने वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार दिखाया है और पंजाब का कर्ज-से-जीडीपी अनुपात लगभग तीन प्रतिशत तक घटा है। उन्होंने राज्य में सिंचाई व्यवस्था और भूजल स्तर सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि आम आदमी क्लीनिकों को जनता, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उद्योग मंत्री अमन अरोरा ने कहा कि पंजाब को 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य में उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दशार्ता है।

झिंझर ने समाना नगर काउंसिल चुनावों दौरान आप पर पुलिस के दुरुपयोग के लगाए आरोप

सिटी दर्पण संवाददाता
समाना

शिरोमणि अकाली दल के यूथ अकाली दल प्रधान और घनौर हलका इंचार्ज सरबजीत सिंह झिंझर ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी पर समाना नगर काउंसिल चुनावों के दौरान पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और वोटरों को दबाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पुलिस को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश की, जबकि आपह्र कार्यकताओं को खुली छूट दी गई। झिंझर ने आरोप लगाया कि शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, पार्टी कार्यकताओं को गिरफ्तार किया गया और दफ्तर को जबरन खाली करवाया गया, जबकि मौके पर मौजूद आप कार्यकताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस, जिसे चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष रक्षक होना चाहिए था, वह आप की एनफोर्समेंट विंग की तरह काम कर रही है और मतदान के दौरान सोच-समझकर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। समाना में जो कुछ हो रहा है, वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है, झिंझर ने कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन को जानबूझकर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब समाना पुलिस ने वोट डालने आए आम वोटरों पर लाठीचार्ज किया, जिसकी अकाली दल की ओर से कड़ी निंदा की गई। झिंझर ने कहा कि चुनाव वाले दिन विपक्षी पार्टियों के कार्यकताओं और वोटरों के खिलाफ की गई यह संयुक्त कार्रवाई साफ दशार्ती है कि आप सरकार लोकतांत्रिक विरोध को सरकारी दबाव और धमकियों के जरिए कुचलना चाहती है।

संक्षिप्त-समाचार

एस.सी. आयोग द्वारा राजा वड़िंग के बयान का लिया सू मोटो नोटिस

चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने कांग्रेस पार्टी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की वायरल वीडियो का सू मोटो नोटिस लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर द्वारा आयोग के ध्यान में लाया गया कि कांग्रेस पार्टी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने चुनाव प्रचार के दौरान दलित जातियों के प्रति जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया है। जिस संबंध में आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री मुक्तसर साहिब से 29 मई 2026 को एस.पी. श्री मुक्तसर साहिब के माध्यम से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की आवाज के सैंपल लेकर फोरेंसिक जांच करवाई जाए तथा उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।

हर सुबह की सुपर शुरूआत: कैलिफोर्निया एल्मोंड्स बेहतर सुबह के पोषण की शक्ति को बढ़ाएं

चंडीगढ़। सुबह पूरे दिन का मिजाज तय करती है, और सही रूटीन बनाने से किसी की भी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ सकता है। सुबह की स्वस्थ आदतों के महत्व को दोहराते हुए, एल्मोंड्स बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया ने चंडीगढ़ के हयात रीजेंसी में एक दिलचस्प और ऊर्जा से भरपूर सेशन आयोजित किया। इस सेशन को ₹हर सुबह की सुपर शुरूआत: कैलिफोर्निया एल्मोंड्स के 24 पोषक तत्वों के साथ।₹ जानी-मानी और लोकप्रिय आरजे मेघा द्वारा संचालित इस सेशन में राष्ट्रीय एथलीट और दो बार की एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता हरमिलन बैंस, और पोषण व वेलनेस सलाहकार शीला कृष्णस्वामी ने सुबह की पौष्टिक आदतों के महत्व पर बातचीत की, और बताया कि कैसे कैलिफोर्निया एल्मोंड्स (बादाम) दिन की सही शुरूआत करने में एक सरल लेकिन शक्तिशाली भूमिका निभा सकते हैं। इस चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि दिन की शुरूआत में हम जो चुनाव करते हैं, वे हमारे समग्र स्वास्थ्य को कैसे आकार दे सकते हैं। अपने निजी अनुभवों से सीखते हुए, पैनलिस्टों ने सरल और लगातार पोषण संबंधी आदतों की शक्ति के बारे में बात की–जिसमें रोजाना के आहार में कैलिफोर्निया बादाम को शामिल करना भी शामिल है। उन्होंने यह साबित किया कि स्वास्थ्य में सार्थक बदलाव लाने के लिए खानपान का जटिल होना जरूरी नहीं है–इसकी शुरूआत आपकी प्लेट में रखी किसी बहुत ही सरल चीज से भी हो सकती है।

चढ़दी कला की स्टारकास्ट ने पत्रकारों संग किया लंच, साझा किए फिल्म के दिलचस्प पहलू

मोहाली। पंजाबी फिल्म चढ़दीकला की स्टारकास्ट ने पत्रकारों के साथ विशेष लंच मीट का आयोजन कर फिल्म प्रमोशन को एक अलग और यादगार अंदाज दिया। इस दौरान फिल्म के कलाकार ऐमी विर्क, रूपी गिल, हिम्मत संधू, जरनैल सिंह और प्रोड्यूसर गुरकरण धालीवाल ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ खुलकर बातचीत की और फिल्म से जुड़े कई रोचक अनुभव साझा किए।स्टारकास्ट ने बताया कि चढ़दीकला एक पीरियड फिल्म है, जिसकी कहानी दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के साथ-साथ पंजाब की संस्कृति, संघर्ष और ह्लचढ़दी कलाह्व की भावना को बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी। कलाकारों ने कहा कि फिल्म के हर किरदार और दृश्य को वास्तविक बनाने के लिए पूरी टीम ने काफी मेहनत की है। पत्रकारों के साथ हुए इस अनौपचारिक संवाद में फिल्म की मेकिंग, संगीत, लोकेशंस और कलाकारों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। कलाकारों ने कहा कि दर्शकों को फिल्म में मनोरंजन के साथ एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस होगा। फिल्म की पूरी टीम ने उम्मीद जताई कि चढ़दीकला पंजाबी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाएगी और दर्शकों को एक नया सिनेमाई अनुभव देने में सफल रहेगी।

अभिनेता योगराज को चंडीगढ़ जिला अदालत से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

चंडीगढ़। पंजाब से जुड़े एक्टर और पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह को चंडीगढ़ जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है। महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब योगराज सिंह ने मामले में राहत के लिए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। मामला सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों में कथित तौर पर महिलाओं पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज

की गई थी। पुलिस ने मामले में प्रारंभिक जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी और इसी दौरान अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब पूरा मामला उच्च न्यायालय में जाने की संभावना है, जहां योगराज सिंह की ओर से राहत की मांग की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कोर्ट के आगामी फैसलों पर निर्भर करेगी। चंडीगढ़ के दो एडवोकेट उज्वल भसीन और जतिन वर्मा ने इस मामले में एसएसपी को शिकायत दी थी कि सोशल मीडिया पर 17 सेकेंड की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया।

आयकर विभाग (इंटेलिजेंस एवं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन) निदेशालय, चंडीगढ़, द्वारा नए आयकर अधिनियम, 2025 एवं नए आयकर नियम, 2026 पर जागरूकता कार्यक्रम

चंडीगढ़। आयकर विभाग (इंटेलिजेंस एवं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन) निदेशालय, चंडीगढ़ द्वारा ढफ्रअफ्रअटइल, 2026 के राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत दिनांक 25.05.2026 को चंडीगढ़ एवं फरीदाबाद में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम श्री रोहित शर्मा, निदेशक आयकर चंडीगढ़ तथा श्रीमती गगन कुंद्रा, अतिरिक्त निदेशक आयकर चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान चंडीगढ़ शाखा एवं फरीदाबाद शाखा के सहयोग से किया गया। इस संगोष्ठी में सदस्यों, बार एसोसिएशन के सदस्यों, बैंकरों एवं तहसीलदारों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम का उद्देश्य नए आयकर अधिनियम, 2025 एवं नए आयकर नियम, 2026 तथा निदेशालय से संबंधित फाइलिंग हेतु नए प्रपत्र 97, 98, 165, 166 एवं 167 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टता प्रदान करना था। इस जागरूकता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग अक-सक्षम करसाथीह्व चैटबॉट का प्रदर्शन था। उपस्थित प्रतिभागियों को चैटबॉट की कार्यप्रणाली एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई तथा बताया गया कि सक्षम चैटबॉट कर साथी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी उद्देश्य से कर साथी पर एक विशेष डेस्क भी स्थापित की गई, ताकि प्रतिभागियों को आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध नए अक टूल्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके। संगोष्ठी के दौरान श्रीमती सरिता अग्रवाल, सहायक निदेशक आयकर चंडीगढ़ ने नए आयकर अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताओं, निदेशालय की भूमिका फाइलिंग से संबंधित अनुपालन आवश्यकताओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। वहीं फरीदाबाद में श्री विकास परिहार, आयकर अधिकारी फरीदाबाद ने सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें श्रीमती सरिता अग्रवाल, क्र्र ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर एवं स्पष्टीकरण प्रदान किए। कार्यक्रम का समापन हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल देते हुए किया गया।

फिरोजपुर में 5 ग्लॉक पिस्तौल समेत हथियार सप्लायर काबू

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/फिरोजपुर

- सीमा पार से चैनलों के माध्यम से भारत में तस्करी किए गए हथियार बरामद: डीजीपी गौरव यादव
- गिरफ्तार किए गए आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और वह एक माह पहले ही जेल से रिहा हुआ था: एआईजी सीआई गुरसेवक सिंह

पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता में काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) फिरोजपुर ने एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का पदार्फाश किया है तथा उसके कब्जे से पांच .30 बोर ग्लॉक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान लखविंदर सिंह निवासी गांव खेड़ा के उत्तर, फिरोजपुर के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और वह मात्र एक माह पहले ही जेल से रिहा हुआ था। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बरामद किए गए हथियार कथित तौर पर सीमा पार से चैनलों के माध्यम से भारत में तस्करी करके लाए गए थे और इन्हें नेटवर्क के जरिए आगे पहुंचाने की योजना थी।

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है ताकि मॉड्यूल से जुड़े सभी व्यक्तियों की पहचान की जा सके।

इस ऑपरेशन संबंधी जानकारी साझा करते हुए एआईजी सीआई फिरोजपुर गुरसेवक सिंह ने कहा कि पुलिस टीमों को संदिग्ध लखविंदर सिंह द्वारा क्षेत्र में हथियार सप्लाई किए जाने संबंधी विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी।

तेजी से कार्रवाई करते हुए सीआई फिरोजपुर की पुलिस टीम ने फिरोजपुर के कुलगढ़ी क्षेत्र में गुप्त अभियान चलाकर लखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे बताया कि उसकी तलाशी के दौरान पुलिस पार्टी ने पांच आधुनिक हथियारों की खेप बरामद की।

एआईजी ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी ने ये हथियार अपने हैंडलर के निर्देशों पर आपराधिक समूहों के सदस्यों को सप्लाई करने थे। उन्होंने कहा कि जांच आगे बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगी होने की संभावना है। इस संबंध में थाना कुलगढ़ी, फिरोजपुर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 103 दिनांक 25-05-2026 दर्ज की गई है।

चुनाव में कुल 7555 उम्मीदवार मैदान में

पंजाब नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान में दिखा जबरदस्त उत्साह

एजेंसी (हि.स.)
चंडीगढ़

पंजाब में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए आज सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राज्य में हो रहे इन स्थानीय निकाय चुनावों को वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन चुनावों में कुल 7555 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना और परिणाम 29 मई को घोषित किए जाएंगे। कुल उम्मीदवारों में से 79 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए कुल 35,45,567 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 18,33,712 पुरुष, 17,11,635 महिलाएं और 220 अन्य मतदाता शामिल हैं। राजनीतिक दलों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सबसे अधिक 1,801 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 1,316, कांग्रेस के 1,550, शिरोमणि अकाली दल के 1,251 और बहुजन समाज पार्टी के 96 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 1,528 निर्दलीय और 13 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं।

मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पोलिंग स्टेशनों और संवेदनशील क्षेत्रों में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 740 बूथों को संवेदनशील और 275 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इन चुनावों के लिए करीब 35,000 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 32,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता शाम 5 बजे तक मतदान केंद्र परिसर में पहुंच जाएंगे, उन्हें वोट डालने का अवसर दिया जाएगा।

नगर काउंसिल दीनानगर, गुरदासपुर, कादियां और शाम चौरासी के सदस्यों के चुनाव हेतु चुनाव 13 जून को होंगे

चंडीगढ़। स्थानीय निकाय विभाग, पंजाब द्वारा पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट, 1911 की धारा 13-ए के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 03/01/इलेक्शन्स(एस-2)/एमईबी/2026/78 दिनांक 21.05.2026 के अनुसार राज्य चुनाव आयोग, पंजाब ने नगर काउंसिल दीनानगर, नगर काउंसिल गुरदासपुर, नगर काउंसिल कादियां तथा नगर काउंसिल शाम चौरासी के सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव करवाने की तिथियों की घोषणा कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 30.05.2026 (शनिवार) को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में दाखिल किए जाने शुरू होंगे और अंतिम तिथि 03.06.2026 (बुधवार) दोपहर 03:00 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 04.06.2026 (वीरवार) को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 05.06.2026 (शुक्रवार) दोपहर 03:00 बजे तक होगी। इन नगर काउंसिलों के चुनाव 13.06.2026 (शनिवार) को सुबह 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक करवाए जाएंगे। मतदान के तुरंत बाद उसी दिन मतों की गिनती की जाएगी। आयोग ने इन चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन नगर काउंसिलों के अधिकार क्षेत्र में, जहां चुनाव होने हैं, आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

राजा भोज और रानी कमलापति के सम्मान में जारी होंगे स्मारक डाक टिकट: सिंधिया

कहा, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक चेतना को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम

एजेंसी (हि.स.)
भोपाल

स्मारक डाक टिकट राष्ट्र की विरासत को संरक्षित करने का माध्यमः केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महान परमार शासक सम्राट राजा भोज और गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना महारानी कमलापति के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने को भारत के सांस्कृतिक गौरव और मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक बताया है।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राजा भोज और रानी कमलापति हमारे भोपाल की गौरवशाली विरासत, संस्कृति और ऐतिहासिक अस्मिता के अभिन्न प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ह्वविकास भी, विरासत भीह्व के मंत्र के साथ देश अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को नया सम्मान दे रहा है। उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाना केवल एक औपचारिक सम्मान नहीं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का सशक्त प्रयास है।

सिंधिया ने कहा कि स्मारक डाक टिकट केवल प्रतीकात्मक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि सामूहिक स्मृति को संरक्षित करने और पीढ़ियों से नागरिकों के बीच राष्ट्र की विरासत के प्रति जागरूकता फैलाने के शक्तिशाली साधन हैं। उन्होंने कहा कि राजा भोज और रानी कमलापति को समर्पित डाक टिकटों का विमोचन भारत के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और समाज में उनके अमिट योगदान के प्रति जन जागरूकता को मजबूत करने में सहायक होगा।

फोटोः हि.स.

गौरतलब है कि भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने सम्राट राजा भोज और वीरांगना महारानी कमलापति के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने इन दोनों महान विभूतियों के नाम पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने का आग्रह किया था, ताकि उनके ऐतिहासिक योगदान और राष्ट्र निर्माण में निभाई गई भूमिका को स्थायी पहचान मिल सके।

राजा भोज भारतीय इतिहास के ऐसे शासक थे, जिन्होंने शिक्षा साहित्य , संस्कृति, स्थापत्य कला, जल प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। भोपाल का बड़ा तालाब सहित कई ऐतिहासिक जल संरचनाएं उनकी दूरदर्शिता और जनकल्याणकारी सोच का प्रतीक हैं। वहीं, महारानी कमलापति ने भी साहस, नेतृत्व और जनसेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और इतिहास के गौरवशाली अध्यायों से युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सिंधिया ने पंत और डॉ. व्यास को पद्मश्री से सम्मानित होने पर दी बधाई

केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मान होने वाली मध्य प्रदेश की दोनों विभूतियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि हमारे मध्य प्रदेश के गौरव कैलाश चंद्र पंत को साहित्य एवं शिक्षा तथा डॉ. नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में 'पद्मश्री' से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि आप दोनों ने अपने समर्पण, ज्ञान और अथक साधना से न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह सम्मान आपकी जीवनपर्यंत तपस्या, भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को समर्पित है। मेरी सुभेक्षा है कि आपकी यह उपलब्धि नई पीढ़ी को सीखने, शोध करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देती रहे।

देवभूमि के वीरों का कमाल, जवानों ने 20 दिन में फतह किया एवरेस्ट

एजेंसी (हि.स.)
देहरादून

फोटोः हि.स.

उत्तराखंड के जवानों ने एक बार फिर साहस, अनुशासन और नेतृत्व का परिचय देते हुए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर नया इतिहास रच दिया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) की 16 सदस्यीय टीम ने 23 मई को प्रातः 3:26 बजे नेपाल समयानुसार 8,848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया। विशेष बात यह रही कि टीम ने काठमांडू से मात्र 20 दिनों में शिखर तक पहुंचकर दुर्लभ उपलब्धि हासिल की।

अभियान का नेतृत्व देहरादून निवासी मेजर अखिलेश भट्ट ने किया, जो मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के घनसाली क्षेत्र के निवासी हैं। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के कई जवानों ने एवरेस्ट फतह कर राज्य का गौरव बढ़ाया। अभियान के उप-नेता की जिम्मेदारी पौड़ी गढ़वाल के सूबेदार सुरेश कुमार बेबनी ने संभाली। शिखर तक पहुंचने वाले उत्तराखंड के अन्य वीर जवानों में चमोली के नायक राहुल सिंह, अल्मोड़ा के नायक पंकज सिंह दोसाद और उत्तरकाशी के कमांडो गौतम बुटोला शामिल रहे। मेजर अखिलेश भट्ट ने बताया कि इस सफलता के पीछे लंबे समय तक चला कठिन प्रशिक्षण और रणनीतिक तैयारी रही। अक्तूबर 2025 में मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में टीम ने गढ़वाल हिमालय स्थित माउंट सतोपंथ (7075 मीटर) का आरोहण किया था। इसके बाद लाहौल-स्पीति क्षेत्र में डोगरा स्काउट्स के साथ कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण लेकर माउंट कानामो (5975 मीटर) पर भी सफलता प्राप्त की गई। एनएसजी के प्रवक्ता के अनुसार यह अभियान संगठन के ध्येय 'सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा' का जीवंत उदाहरण है। विषम परिस्थितियों में टीम को सुरक्षित रूप से शिखर तक पहुंचाना मेजर अखिलेश भट्ट और उनकी टीम के नेतृत्व, तकनीकी दक्षता और अदम्य साहस को दर्शाता है। उत्तराखंड के इन वीर सपूतों की उपलब्धि ने प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को गौरवान्वित किया है। एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगे के साथ देवभूमि का स्वाभिमान लहराकर इन जवानों ने युवाओं को यह संदेश दिया है कि दृढ़ संकल्प और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं।

उन्नाव एक्सप्रेस-वे पर पलटी डबल डेकर बस सीवान के दरोगा और कैदी समेत पांच की मौत

एजेंसी (हि.स.)
सीवान (बिहार)

कई पुलिसकर्मी घायल

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मंगलवार सुबह लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर डबल डेकर एसी बस पलटने से सीवान पुलिस लाइन में तैनात एक दरोगा और एक कैदी समेत पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे में तीन पुलिसकर्मियों सहित 15 लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, सीवान मंडल जेल में बंद हत्या के आरोपित कैदी छत्तरपाल सिंह तोमर को पेशी के लिए पुलिस टीम गुरुग्राम कोर्ट लेकर गई थी। पेशी के बाद पुलिस टीम बस से वापस लौट रही थी। इसी दौरान मंगलवार की सुबह करीब पांच बजे उन्नाव के पास लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मृतकों की पहचान सीवान पुलिस लाइन में तैनात दरोगा रामचंद्र राम (59) तथा गुरुग्राम निवासी कैदी छत्तरपाल सिंह तोमर (59) के रूप में हुई है। तीन अन्य मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आने से हादसा होने की बात सामने आई है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस और राहत टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सीवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि मंडल कारागार के कैदी को गुरुग्राम कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था। वापसी के दौरान उन्नाव में बस हादसे में दरोगा और कैदी की मौत हो गई। अन्य घायल पुलिसकर्मियों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है।

लेबनान के समर्थन में ईरान, अराघची ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर दोहराया रुख

तेहरान। ईरान ने लेबनान के समर्थन में अपना रुख दोहराते हुए कहा है कि वह क्षेत्रीय तनाव के बीच लेबनान की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के साथ मजबूती से खड़ा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस संबंध में लेबनान के शीर्ष नेताओं को संदेश भेजकर समर्थन व्यक्त किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लेबनानी संसद स्पीकर नबीह बेरी और हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम को रेजिस्टेंस एंड लिबरेशन डे पर संदेश भेजकर लेबनान की सरकार, जनता और रेजिस्टेंस को बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने लेबनान की सरकार, जनता और प्रतिरोध समूहों की भूमिका की सराहना की। यह दिवस वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजराइली सेना की वापसी की याद में मनाया जाता है और लेबनान में इसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर माना जाता है। ईरान का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब क्षेत्रीय हालात पहले से तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हिजबुल्लाह की आलोचना करते हुए उस पर लेबनान-इजराइल वार्ता प्रक्रिया में सहयोग न करने के आरोप लगाए थे। उधर, अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं।

पेट्रो पदार्थों की महंगाई पर कांग्रेस हमलावर खरगे बोले- जनता को राहत क्यों नहीं

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। खरगे ने सवाल किया कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तो जनता को राहत क्यों नहीं दी गई।

खरगे ने मंगलवार को एक्स पर सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पदभार संभाला था, उस समय भारतीय बास्केट का कच्चा तेल 108.05 डॉलर प्रति बैरल था और डॉलर-रुपया विनिमय दर 58.59 रुपये थी। उस समय पेट्रोल 71.51 रुपये और डीजल 56.71 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था। खरगे ने

फोटोः हि.स.

कहा कि वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत 99 डॉलर प्रति बैरल से नीचे है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़कर क्रमशः 102.12 रुपये और 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इस अवधि में पेट्रोल लगभग 42.8 प्रतिशत और डीजल करीब 67.9 प्रतिशत महंगा हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर परिवहन, खाद्य वस्तुओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर पड़ता है, जिससे आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता है।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देउवा और उनकी पत्नी के गिरफ्तारी आदेश पर अंतरिम रोक

काठमांडू। नेपाल के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी डॉ. आरजू राणा देउवा की गिरफ्तारी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति महेश शर्मा पौडेल और न्यायमूर्ति नित्यानंद पाण्डेय की संयुक्त पीठ ने सरकार के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। देउवा दंपत्ति इस समय हांगकांग में हैं। इससे पहले इंटरपोल ने भी कथित तौर पर इस मामले में सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। 19 मई को न्यायाधीश मेघराज पोखरेल की पीठ ने इसी मामले में कारण बताओ आदेश जारी करते हुए सरकार को 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग विभाग ने काठमांडू जिला अदालत से देउबा को गिरफ्तार करने की अनुमति प्राप्त की थी।

मोथाबाड़ी न्यायाधीश उत्पीड़न मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 14 और गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मोथाबाड़ी न्यायाधीश उत्पीड़न मामले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तेजी ला दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार देररात मालदा जिले के कालियाचक और मोथाबाड़ी के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए आज इन लोगों को अदालत में पेश कर हिरासत की मांग करेगी। जांच एजेंसी का मानना है कि इनसे पूछताछ में इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सकेगी। दरअसल, राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कालियाचक के मोथाबाड़ी क्षेत्र में स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई थी। आरोप था कि सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर बीडीओ कार्यालय में एसआईआर कार्य के लिए पहुंचे न्यायाधीशों को कई घंटों तक घेर कर रखा गया। भीड़ ने न्यायाधीशों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि देर रात केंद्रीय बलों की सुरक्षा में सात न्यायाधीशों को किसी तरह वहां से निकाला गया। इनमें एक महिला न्यायाधीश भी शामिल थीं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। एजेंसी इस मामले में दर्ज तीन प्राथमिकी के आधार पर जांच कर रही है। इस घटना के बाद मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के आईएसएफ उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली कादरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि

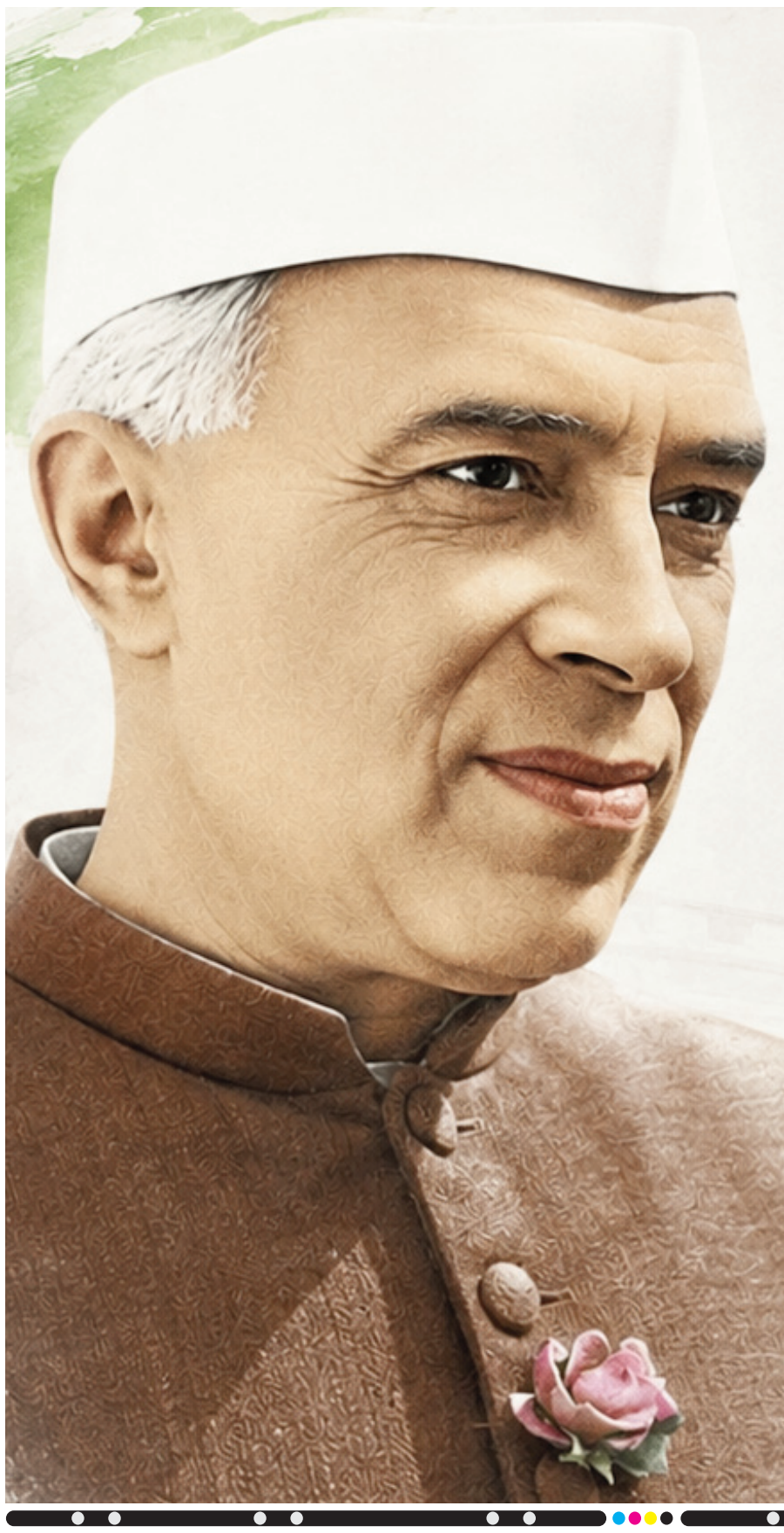

पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद के एक धनाढ्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूपरानी था। पिता पेशे से वकील थे। उनकी 3 पुत्रियां थीं और जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चों के प्यारे 'चाचा नेहरू' के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले खास पथप्रदर्शक थे। जवाहरलाल नेहरू को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज, लंदन से पूरी की थी। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर 1912 में नेहरूजी ने बार-एट-लॉ की उपाधि ग्रहण की और वे बार में बुलाए गए। पंडित नेहरू शुरू से ही गांधीजी से प्रभावित रहे और 1912 में कांग्रेस से जुड़े। 1920 के प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे को संगठित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू घायल हुए और 1930 के नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। उन्होंने 6 माह जेल काटी। 1935 में अलमोड़ा जेल में 'आत्मकथा' लिखी। उन्होंने कुल 9 बार जेल यात्राएं कीं। उन्होंने विश्वभ्रमण किया और वे अंतरराष्ट्रीय नायक के रूप में पहचाने गए। उन्होंने 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद (लाहौर 1929, लखनऊ 1936, फैजपुर 1937, दिल्ली 1951, हैदराबाद 1953 और कल्याणी 1954) को सुशोभित किया। 1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन में नेहरूजी 9 अगस्त 1942 को बंबई में गिरफ्तार हुए और अहमदनगर जेल में रहे, जहां से 15 जून 1945 को रिहा किए गए। नेहरू ने 'पंचशील' का सिद्धांत प्रतिपादित किया और 1954 में 'भारतरत्न' से अलंकृत हुए नेहरूजी ने तटस्थ राष्ट्रों को संगठित किया और उनका नेतृत्व किया। सन- 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत मिले थे, किंतु महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। 'स्वाधीनता और स्वाधीनता की लड़ाई को चलाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई का खास प्रस्ताव तो करीब-करीब एकमत से पास हो गया। ...खास प्रस्ताव इत्तफाक से 31 दिसंबर की आधी रात के घंटे की चोट के साथ, जबकि पिछला साल गुजरकर उसकी जगह नया साल आ रहा था, मंजूर हुआ।' -लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित होने के बारे में नेहरू की 'मेरी कहानी' से। नेहरू के कार्यकाल में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, राष्ट्र और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को स्थायी भाव प्रदान करना और योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को सुचारु करना उनके मुख्य उद्देश्य रहे। नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। उन्होंने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू के लिए एक बड़ा झटका था और शायद इसी वजह से उनकी मौत भी हुई। आजादी के पहले गठित अंतरिम सरकार और आजादी के बाद 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनके निधन तक वे इस पद पर बने रहे। जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ा जिसमें उनकी मृत्यु हो गई।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका

विदेश नीति के क्षेत्र में भी नेहरू की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया दो बड़े गुटों में बंटी हुई थी, तब उन्होंने भारत को गुटनिरपेक्ष नीति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। मित्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज टीटो और अन्य नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत किया। नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य भारत की स्वतंत्र पहचान बनाए रखना और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना था। पंचशील सिद्धांत भी उनकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। हालांकि, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद उनकी नीतियों की आलोचना भी हुई, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्वतंत्र और संतुलित पहचान स्थापित करने में उनके योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से विशेष स्नेह रखते थे। बच्चे उन्हें प्यार से 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को देशभर में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू का मानना था कि राष्ट्र का भविष्य बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कारों पर निर्भर करता है।

साहित्य और लेखन में भी गहरी रुचि

नेहरू केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि गंभीर लेखक भी थे। जेल में रहते हुए उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया', 'ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' और 'एन ऑटोबायोग्राफी' प्रमुख हैं। इन पुस्तकों में इतिहास, राजनीति और भारतीय सभ्यता को लेकर उनके विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नेहरू की आर्थिक नीतियों को लेकर समय-समय पर विभिन्न मत सामने आते रहे हैं। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका तय की गई। उस दौर में संसाधनों की कमी और औद्योगिक आधार के अभाव को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

संसद और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता

पंडित नेहरू संसदीय परंपराओं के मजबूत समर्थक थे। प्रधानमंत्री रहते हुए वे संसद में नियमित रूप से उपस्थित रहते थे और विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि संवाद और जवाबदेही उसकी मूल आत्मा है। नेहरू ने भारत में धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक विविधता को भी विशेष महत्व दिया। उनका मानना था कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित है। उन्होंने संविधान में निहित समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिक तनाव और विभाजन की परिस्थितियों के बीच उन्होंने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का प्रयास किया। उनकी पुण्यतिथि पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक मंचों पर आयोजित कार्यक्रमों में उनके विचारों और योगदान पर चर्चा की गई। कई स्थानों पर संगोष्ठियों, विचार गोष्ठियों और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। विद्यार्थियों और युवाओं को लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेहरू का व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत की संस्थाओं के निर्माण तक उनकी भूमिका बहुआयामी रही। उनके समर्थक उन्हें आधुनिक भारत का वास्तुकार मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी कुछ नीतियों पर प्रश्न उठाते रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय लोकतंत्र, शिक्षा और वैज्ञानिक विकास की दिशा तय करने में उनकी भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

शांति वन में हर वर्ष श्रद्धांजलि

दिल्ली स्थित शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की उनकी सोच को याद किया जाता है। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। उनके निधन के साथ भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण युग का अंत माना गया। उस समय देशभर में शोक की लहर दौड़ गई थी। लाखों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। आज भी उनकी पुण्यतिथि पर देश उनके योगदान को स्मरण करता है और आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक चुनौतियों के बीच जिस नेतृत्व ने लोकतंत्र, विकास और आधुनिकता की दिशा तय की, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनकी नीतियों और विचारों पर मतभेद संभव हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनके योगदान को इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी पुण्यतिथि केवल एक नेता को श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय एकता के महत्व को पुनः स्मरण करने का भी अवसर है।

खेल प्रशासन में बड़ा सुधार: राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल न्यायाधिकरण के नियम अधिसूचित

अब खेल संघों पर होगी कड़ी निगरानी, खिलाड़ियों और संस्थाओं को मिलेगा तेज व सस्ता न्याय

- राष्ट्रीय खेल बोर्ड करेगा खेल संघों की निगरानी
- खेल विवादों के लिए बनेगा विशेष न्यायाधिकरण

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने भारतीय खेल व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम 2026 और राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है।

प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से मंगलवार सुबह जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार

फोटोः हि.स.

इन नए नियमों के लागू होने के बाद देश में खेल संघों की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और खेल विवादों के निपटारे की व्यवस्था पूरी तरह बदलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे खेल प्रशासन अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और पेशेवर बनेगा। नए नियमों के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

यह बोर्ड देश के राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने, उनके प्रशासनिक ढांचे, वित्तीय पारदर्शिता और नैतिक मानकों की निगरानी करने का कार्य करेगा। सरकार के अनुसार अब खेल संघों को बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय अनुशासन का पालन करना होगा। सरकार ने खेलों से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण बनाने का भी फैसला किया है। यह न्यायाधिकरण खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल संघों और अन्य हितधारकों से जुड़े विवादों की सुनवाई करेगा। इसका उद्देश्य दीवानी अदालतों पर निर्भरता कम करना और कम खर्च में तेज न्याय उपलब्ध कराना है।

ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

नए नियमों में डिजिटल व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है। केंद्र सरकार एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगी, जहां विवाद दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने, जवाब दाखिल करने और आदेश देखने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा वर्चुअल सुनवाई और ऑनलाइन रिकॉर्ड प्रबंधन की भी व्यवस्था होगी।

खेल व्यवस्था को मिलेगा नया ढांचा

सरकार का कहना है कि ये नियम भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम हैं। इससे खिलाड़ियों को बेहतर माहौल, खेल संस्थाओं में पारदर्शिता और विवादों के त्वरित समाधान का लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह भारतीय खेल प्रशासन में अब तक के सबसे बड़े संस्थागत सुधारों में से एक माना जा रहा है।

बुंडेसलीगा से 29 साल बाद बाहर हुआ फुटबॉल क्लब वोल्फ्सबर्ग

- पैडरबोर्न ने अतिरिक्त समय में दर्ज की ऐतिहासिक जीत

एजेंसी (हि.स.)
पैडरबोर्न

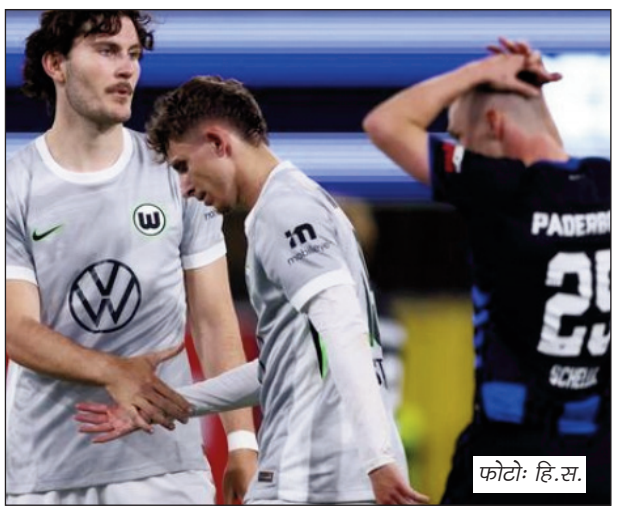
फोटोः हि.स.

जर्मन फुटबॉल क्लब वोल्फ्सबर्ग 29 वर्षों बाद बुंडेसलीगा से बाहर हो गया। सोमवार को खेले गए रेलिगेशन प्लेऑफ के दूसरे चरण में पैडरबोर्न ने अतिरिक्त समय में 2-1 से जीत दर्ज कर शीर्ष लीग में जगह बना ली। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला गोलरहित ड्रॉ रहा था। दूसरे चरण में वोल्फ्सबर्ग ने तीसरे मिनट में डेजनान पेजचिनोविच के गोल की बदौलत बढ़त बना ली थी, लेकिन पैडरबोर्न ने पहले हाफ खत्म होने से सात मिनट पहले फिलिप बिलबिजा के गोल से बराबरी कर ली।

मुकाबले में वोल्फ्सबर्ग की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब जोआकिम मेहले को शुरूआती गोल के केवल 11 मिनट बाद रेड कार्ड दिखाया गया। उन्हें तीन मिनट के भीतर दो पीले कार्ड मिले और टीम को लगभग पूरा मैच 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसके बाद पैडरबोर्न ने लगातार आक्रमण किए, लेकिन वोल्फ्सबर्ग के गोलकीपर कामिल ग्राबारा ने कई शानदार बचाव कर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 रहने के बाद मैच अतिरिक्त समय में पहुंचा।

अतिरिक्त समय के 10वें मिनट में लॉरिन कुर्डा ने शानदार वॉली गोल दागकर पैडरबोर्न को निर्णायक बढ़त दिलाई। यही गोल टीम की ऐतिहासिक जीत का कारण बना और पैडरबोर्न ने तीसरी बार बुंडेसलीगा में प्रवेश किया। वोल्फ्सबर्ग 1997 में पहली बार बुंडेसलीगा में पहुंचा था और तब से लगातार शीर्ष लीग का हिस्सा रहा। क्लब ने 2009 में बुंडेसलीगा खिताब और 2015 में जर्मन कप जीता था। वहीं पैडरबोर्न की इससे पहले बुंडेसलीगा में दो बार एंट्री हुई थी, लेकिन दोनों मौकों पर टीम अगले ही सत्र में बाहर हो गई थी।

फीफा विश्व कप 2026 के लिए कोलंबिया टीम घोषित, जेम्स रोड्रिगेज को मिली जगह

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

कोलंबिया ने सोमवार को फीफा विश्व कप 2026 के लिए अपनी 26 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। टीम में पूर्व रियल मैड्रिड स्टार जेम्स रोड्रिगेज को शामिल किया गया है, जबकि अल नास्र के डिफेंडर जॉन दुरान को जगह नहीं मिली। मुख्य कोच नेस्टर लोरेन्जो की टीम में बायर्न म्यूनिख के स्टार फॉरवर्ड लुइस डियाज सबसे बड़े आकर्षण होंगे। कोलंबिया इस बार पहली बार विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। कोलंबिया वर्ष 2022 विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया था।

वहीं 2018 विश्व कप में टीम इंग्लैंड के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में हारकर प्री-क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई थी। कोलंबिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 विश्व कप में रहा था, जब टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी और ब्राजील से हार गई थी। विश्व कप 2026 में कोलंबिया को ग्रुप-के में

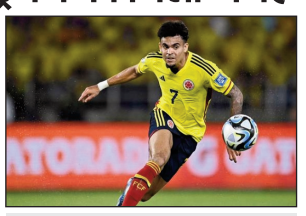

कोलंबिया की टीम

गोलकीपरः कैमिलो वर्गास, अल्वारो मोंटेरो, डेविड ओस्पिना

डिफेंडरः डेविंसन सांचेज, जॉन लुकुमी, येरी मीना, विलियम डिड्डा, डेनियल मुनोज, सैंटियागो आरियास, जोहान मोजिका, डेविन मचाडो

मिडफील्डरः जेफरसन लेर्मा, जुआन पोर्टिला, रिचर्ड रियोस, केविन कास्टानो, गुस्तावो पुर्ता, जॉन एरियास, जॉर्ज कारास्कल, जुआन फर्नांडो किंटेरो, जेम्स रोड्रिगेज

फॉरवर्डः लुइस डियाज, जामिंटन कैंपाज, एंड्रेस गोमेज, लुइस सुआरेज, जॉन कॉडोबा, जॉन हर्नांडिज।

रखा गया है, जहां उसका मुकाबला पुर्तगाल, उज्बेकिस्तान और डीआर कांगो से होगा।

अंडर-18 एशिया कप के लिए जापान रवाना हुई भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें

- केतन कुशवाहा और स्वीटी कुजूर संभालेंगे भारतीय टीमों की कमान

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

भारतीय अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी टीमें अंडर-18 एशिया कप 2026 में भाग लेने के लिए जापान के काकामिगाहारा रवाना हो गई हैं। यह टूर्नामेंट 29 मई से 6 जून तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय पुरुष टीम सोमवार शाम को दिल्ली से रवाना हुई, जबकि महिला टीम मंगलवार सुबह जापान के लिए रवाना हुई। दोनों टीमें भोपाल में आयोजित लंबे राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अभ्यास मुकाबलों के बाद टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रही हैं। पुरुष टीम के कोचिंग स्टाफ में सरदार सिंह और रजनीश मिश्रा शामिल हैं, जबकि भारतीय महिला टीम की कोच पूर्व कप्तान रानी हैं। एशिया कप की तैयारी के तहत भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने भोपाल में ऑस्ट्रेलिया अंडर-18 टीमों के खिलाफ चार-चार अभ्यास मुकाबले खेले। भारतीय पुरुष टीम ने एक मुकाबला जीता, एक हारा, जबकि दो मैच ड्रॉ रहे। वहीं भारतीय महिला टीम ने श्रृंखला का समापन शानदार जीत के साथ किया। इन मुकाबलों से खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिला।

फॉरवर्ड खिलाड़ी केतन कुशवाहा भारतीय पुरुष टीम की कप्तानी करेंगे। भारत को पूल-ए में रखा गया है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरूआत 29 मई को कजाखस्तान के खिलाफ करेगी। इसके बाद टीम जापान (31 मई), कोरिया (1 जून) और चीनी ताइपे (3 जून) से भिड़ेगी। पूल-बी में मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की टीमें शामिल हैं। दोनों पूलों की शीर्ष दो टीमें 5 जून को होने वाले सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जबकि फाइनल मुकाबला 6 जून को खेला जाएगा। कप्तान केतन कुशवाहा ने कहा, भारत का प्रतिनिधित्व करना हमारे लिए गर्व की बात है। भोपाल शिविर और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबलों से हमें काफी सीख मिली। टीम का तालमेल शानदार है और हम एशिया की मजबूत टीमों के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।

स्वीटी कुजूर के नेतृत्व में उतरेगी महिला टीम

भारतीय महिला टीम की कप्तानी स्वीटी कुजूर करेंगी। महिला टीम को भी पूल-ए में रखा गया है। भारत अपना पहला मुकाबला 30 मई को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद 31 मई को कोरिया और 2 जून को सिंगापुर से मुकाबला होगा। दोनों पूलों की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। कप्तान स्वीटी कुजूर ने कहा, पूरी टीम एशिया कप को लेकर उत्साहित और आत्मविश्वास से भरी है। हमने शिविर में कड़ी मेहनत की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबलों से हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का पता चला। श्रृंखला जीतने से हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा है। हम भारत को गौरवान्वित करने के लिए पूरा दम लगाएंगे।

मेग लैनिंग ने विक्टोरिया अनुबंध छोड़ अपनाया फ्रीलांस क्रिकेटर का रास्ता

एजेंसी (हि.स.)
मेलबर्न

ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग ने अगले सत्र के लिए विक्टोरिया का अनुबंध नहीं लेने का फैसला किया है और अब वह फ्रीलांस क्रिकेटर के रूप में खेलती नजर आएंगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी लैनिंग विक्टोरिया टीम का हिस्सा बनी हुई थीं, लेकिन पिछले सत्र में उन्होंने टीम के लिए केवल चार मुकाबले खेले थे।

महिला बिग बैश लीग के बाद वह किसी भी मैच में नहीं उतरीं। मेग लैनिंग इस समय दुनिया की विभिन्न फ्रेंचाइजी लीगों में खेल रही हैं। वह महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स, द हंड्रेड में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और इस सत्र में लंकाशायर के लिए टी-20 ब्लास्ट में हिस्सा ले चुकी हैं। लैनिंग फिलहाल मेलबर्न स्टार्स के साथ भी अनुबंधित

फोटोः हि.स.

नहीं हैं। हालांकि पिछले महिला बिग बैश लीग सत्र में वह टीम की दूसरी सबसे सफल बल्लेबाज रहीं। उन्होंने 53.22 की औसत और 136.07 के स्ट्राइक रेट से 479 रन बनाए थे। क्रिकेट विक्टोरिया की महिला क्रिकेट प्रमुख किर्बी शॉर्ट ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, हम मेग के फैसले का सम्मान करते हैं। महिला क्रिकेट तेजी से विकसित हो रहा है और खिलाड़ियों को अब दुनिया भर में खेलने के अवसर मिल रहे हैं। यह हमारे खेल के विकास का सकारात्मक संकेत है।

खराब सत्र पर विक्टोरिया ने जताई निराशा

किर्बी शॉर्ट ने स्वीकार किया कि 2025-26 सत्र विक्टोरिया के लिए बेहद निराशाजनक रहा, जहां टीम अपने सभी 12 मुकाबले हार गई थी। उन्होंने कहा, हम पिछले सत्र के परिणामों पर गर्व नहीं कर सकते और हमें पता है कि हमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हालांकि समीक्षा के बाद खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच सकारात्मक माहौल बनाने को लेकर स्पष्ट समझ बनी है।

विक्टोरिया महिला टीम 2026-27 टीम

इरा एरी, सोफी डे, समारा डल्विन, निकोल फाल्टम, टेस फ्लिंटॉफ, किम गर्थ, हसरत गिल, ओलिविया हेनरी, मिली इलिंगवर्थ, रीस मैककेना, सोफी मोलिनेक्स, इंडिगो नोबल, मिया पेरिन, जॉर्जिया प्रेस्टविज, जो सैमुअल, मौली स्ट्रानो, एनाबेल सदरलैंड, टायला व्लेमिन्क, जॉर्जिया वेयरहैम और ब्रोंटे लीशम।

टीमटेक फॉर्मवर्क की स्टॉक मार्केट में प्रीमियम एंट्री, मुनाफे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मॉड्यूलर टी-फॉर्मवर्क और कस्टमाइज्ड फॉर्मवर्क सिस्टम बनाने वाली कंपनी टीमटेक फॉर्मवर्क सॉल्यूशंस के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में प्रीमियम एंट्री कर अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 63 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 19.05 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 75 रुपये के स्तर पर ही हुई।

लिस्टिंग के बाद बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण ये शेयर टूट 71.25 रुपये के लोअर सर्किट लेवल तक गिर गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बना कर लोअर सर्किट ब्रेक कर दिया। दोपहर 12:30 बजे तक का कारोबार होने के बाद कंपनी के शेयर 75 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह अभी तक के कारोबार के बाद कंपनी के आईपीओ निवेशक प्रति शेयर 12 रुपये यानी 19.05 प्रतिशत के फायदे में थे। टीमटेक फॉर्मवर्क सॉल्यूशंस का 50.15 करोड़ रुपये का आईपीओ 19 से 21 मई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 7.01 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 4.28 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 12.79 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 6.10 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 5 रुपये फेस वैल्यू वाले 79.60 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने, प्लांट और मशीनरी खरीदने, पुराने कर्ज के बोझ को कम करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत में लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 7.69 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 7.84 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी शुद्ध लाभ उछल कर 11.59 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

संक्षिप्त-समाचार

शुरूआती कमजोरी के बाद सुधरी शेयर बाजार की चाल, सेंसेक्स और निफ्टी में आई तेजी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार मंगलवार शुरूआती कारोबार में गिरावट का सामना करने के बाद रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। आज के कारोबार की शुरूआत कमजोरी के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिसकी वजह से पहले 15 मिनट के कारोबार के बाद ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक रिकवरी कर हरे निशान में पहुंच गए। इसके बाद मुनाफा वसूली के चक्कर में बाजार को बिकवाली का झटका भी लगा, जिससे इन दोनों सूचकांकों की चाल में दोबारा गिरावट का रुख बन गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही खरीदारों ने दोबारा लिवाली शुरू कर दी, जिससे दोनों सूचकांकों की स्थिति में सुधार होने लगा। पहले एक घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.07 प्रतिशत और निफ्टी 0.13 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरूआती एक घंटे का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से टीएमपीवी, कोल इंडिया, एटरनल, अदानी एंटरप्राइजेज और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर 2.63 प्रतिशत से लेकर 0.73 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, कोटक महिंद्रा, सन फार्मास्युटिकल्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स हेल्थकेयर और अपोलो हॉस्पिटल के शेयर 0.93 प्रतिशत से लेकर 0.77 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,996 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 2,054 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 942 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मंगलवार मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी फिलहाल बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार उत्साह का माहौल बना रहा। वहीं एशियाई बाजार में आज मिला-जुला कारोबार हो रहा है। पश्चिम एशिया में शांति होने की उम्मीद के कारण अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान पॉजिटिव माहौल बना रहा, जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुए। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.37 प्रतिशत उछल कर 7,473.47 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 26,343.97 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 324.76 अंक यानी 0.64 प्रतिशत की छलांग लगा कर 50,904.46 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी बाजार की तरह ही यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार खरीदारी होती रही। एफटीएसई इंडेक्स 0.22 प्रतिशत की मजबूती के साथ 10,466.26 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 172.26 अंक यानी 2.09 प्रतिशत की जोरदार छलांग लगा कर 8,258.26 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 782.33 अंक यानी 3.08 प्रतिशत की जबरदस्त तेजी के साथ 25,389.10 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में आज मिला-जुला कारोबार हो रहा है।

मेस्सी की बायीं हैमस्ट्रिंग में समस्या, इंटर मियामी ने की पुष्टि, अर्जेंटीना की बढ़ी चिंता

मियामी। इंटर मियामी ने स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की बायीं हैमस्ट्रिंग में समस्या होने की पुष्टि की है। विश्व कप चैंपियन अर्जेंटीना के लिए खिताब बचाने के अभियान से पहले मेस्सी की चोट चिंता का विषय बन गई है। क्लब की ओर से जारी जानकारी के अनुसार मेस्सी का सोमवार को चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। हालांकि यह नहीं बताया गया कि कौन-कौन से परीक्षण किए गए, लेकिन जांच में बायीं हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों में समस्या सामने आई है। मेस्सी रविवार को इंटर मियामी के लिए खेलते हुए मैच के दौरान ही मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे। फिलहाल उनकी चोट की गंभीरता और मैदान पर वापसी की समयसीमा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इंटर मियामी ने कहा कि उनकी वापसी पूरी तरह चिकित्सकीय और शारीरिक प्रगति पर निर्भर करेगी। मेस्सी की चोट अर्जेंटीना की विश्व कप तैयारियों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। मेस्सी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह पूरी तरह फिट होने पर ही विश्व कप में हिस्सा लेंगे। अर्जेंटीना को विश्व कप के ग्रुप जे में रखा गया है। टीम अपना पहला मुकाबला 16 जून को कंसास सिटी में अल्जीरिया के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 22 जून को टेक्सास के अर्लिंग्टन में ऑस्ट्रिया और 27 जून को वहीं जॉर्डन से मुकाबला होगा।

फ्रेंच ओपन में राफेल जोडर का दमदार आगाज, पहले दौर में शानदार जीत

पेरिस। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन के उभरते सितारे राफेल जोडर ने शानदार शुरूआत करते हुए पहले दौर में अमेरिका के अलेक्जेंडर कोवासेविच को सीधे सेटों में 6-1, 6-0, 6-4 से पराजित किया। दो बार के मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज के चोट के कारण बाहर होने और फ्रांस के युवा खिलाड़ी आर्थर फिल्स के हटने के बाद 19 वर्षीय जोडर को विश्व नंबर एक यानिक सिनर के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। जोडर ने क्ले कोर्ट पर खेले जा रहे इस ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के अपने पदार्पण मुकाबले में केवल पांच गेम गंवाए। फ्रेंच ओपन में पदार्पण पर इससे कम गेम गंवाने वाले आखिरी खिलाड़ी नोवाक जोकोविच थे, जिन्होंने 2005 में अपने पहले मैच में केवल तीन गेम गंवाए थे। मैच के बाद जोडर ने कहा कि उन्होंने शुरूआत से ही अच्छा प्रदर्शन किया और पिछले कुछ महीनों में काफी कुछ सीखा है। यह उनका एटीपी टूर पर पहला वर्ष है। युवा स्पेनिश खिलाड़ी पिछले 19 मुकाबलों में से 16 जीत चुके हैं। इस दौरान उन्होंने मोरक्को में क्ले कोर्ट खिताब जीता, बार्सिलोना ओपन के सेमीफाइनल और मैड्रिड ओपन के क्वार्टरफाइनल तक पहुंचने में सफलता हासिल की। एक वर्ष पहले जोडर की विश्व रैंकिंग 707 थी, लेकिन अब वह 29वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। फ्रेंच ओपन में उन्हें 27वीं वरीयता मिली है। महिला वर्ग में चार बार की चैंपियन इगा स्वियातेक ने 136वीं रैंकिंग की एमर्सन जोन्स को 6-1, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया।

सर्राफा बाजार में चमका सोना, चांदी में बदलाव नहीं

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में मंगलवार शुरूआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में तेजी का रुख नजर आ रहा है। हालांकि चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में आई तेजी के कारण चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर हिस्सों में सोना 320 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 340 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चेन्नई में सोने की कीमत में 520 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 570 रुपये प्रति 10 ग्राम तक का इजाफा हुआ है।

भाव में आए उछाल के कारण देश के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना मंगलवार 1,59,390 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,61,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,46,110 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,47,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार भी 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही

बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,59,540 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,260 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,59,390 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,46,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,59,440 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,61,250 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,47,810 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है।

नॉर्वे शतरंज

प्रज्ञानानंद, गुकेश और दिव्या ने आमार्गेडन में दर्ज की जीत

भारतीय खिलाड़ियों की शानदार शुरूआत

एजेंसी (हि.स.)
ओस्लो (नॉर्वे)

फोटोः हि.स.

नॉर्वे शतरंज 2026 की शुरूआत रोमांचक मुकाबलों के साथ हुई, जहां पहले ही दौर में क्लासिकल और आमार्गेडन दोनों प्रारूपों में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मजबूत शुरूआत की।

सोमवार को शुरू हुए इस प्रतियोगिता में दिन का सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा ने विश्व नंबर-1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल मुकाबले में हरा दिया। मुकाबले के अधिकांश समय तक कार्लसन मजबूत स्थिति में नजर आ रहे थे, लेकिन समय के दबाव में उनसे बड़ी गलती हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए फिरोजा ने जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ फ्रांसीसी ग्रैंडमास्टर ने प्रतियोगिता में बढ़त बना ली। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद और वेस्ली सो के बीच क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहा। इसके बाद खेले गए आमार्गेडन मुकाबले में प्रज्ञानानंद ने आक्रामक खेल दिखाते हुए जीत हासिल की और अतिरिक्त अंक अपने नाम किए। विश्व चैंपियन डी. गुकेश का सामना जर्मनी के शीर्ष खिलाड़ी विंसेंट कीमर से हुआ। एंडगेम में कीमर मजबूत स्थिति में पहुंच गए थे और जीत के करीब दिखाई दे रहे थे, लेकिन गुकेश ने शानदार बचाव करते हुए मुकाबला ड्रॉ कराया। इसके बाद आमार्गेडन टाईब्रेकर में गुकेश ने वापसी करते हुए जीत दर्ज की और महत्वपूर्ण अतिरिक्त अंक हासिल किए। हले दौर के बाद अलीरेजा फिरोजा क्लासिकल जीत के दम पर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में दिव्या देशमुख की दमदार जीत नॉर्वे शतरंज महिला प्रतियोगिता में भी पहले दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। कजाकिस्तान की बिबिसारा अस्साउबायेवा ने भारत की नंबर-1 खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को क्लासिकल मुकाबले में हराकर बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने मिडिलगेम में मिले अवसरों का शानदार फायदा उठाते हुए सटीक खेल से जीत दर्ज की। अन्ना मुजिचुक और झू जिनर के बीच क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहा, जबकि आमार्गेडन में झू जिनर ने जीत हासिल की। वहीं मौजूदा महिला विश्व चैंपियन जू वेनजुन और भारत की दिव्या देशमुख के बीच क्लासिकल मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। जू वेनजुन जीत के लिए लगातार दबाव बना रही थीं, लेकिन दिव्या ने शानदार संयम दिखाया। इसके बाद आमार्गेडन मुकाबले में दिव्या ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की।

5 जून तक चलेगी प्रतियोगिता

नॉर्वे शतरंज 2026 का आयोजन 25 मई से 5 जून तक ओस्लो में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग के दो सुपर टूर्नामेंट समानांतर रूप से खेले जा रहे हैं। दोनों प्रतियोगिताओं में छह-छह खिलाड़ी डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में हिस्सा ले रहे हैं और दोनों के लिए समान पुरस्कार राशि रखी गई है। इस टूर्नामेंट की खास बात इसका अनोखा प्रारूप है। यदि क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहता है तो विजेता तय करने के लिए आमार्गेडन मुकाबला खेला जाता है, जिससे हर दौर में निर्णायक परिणाम सुनिश्चित होता है।

चंडीगढ़ में आबकारी नीति का पालन न करने वालों के शराब लाइसेंस रद होंगे

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

चंडीगढ़ के सभी शराब लाइसेंसधारकों की एक बैठक उपायुक्त-सह-आबकारी आयुक्त, चंडीगढ़, श्री निशांत कुमार यादव, आईएएस की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आबकारी नीति के अनुपालन की समीक्षा करना तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हाल ही में सामने आए उल्लंघनों पर चर्चा करना था। बैठक के दौरान उपायुक्त-सह-आबकारी आयुक्त ने सोशल मीडिया एप्लिकेशन पर प्रसारित एक रील का गंभीर संज्ञान लिया, जिसमें एक शराब विक्रेता ब्रांड प्रमोशन के नाम पर मुफ्त में शराब परोसता पाया गया। अध्यक्ष ने बताया कि उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है तथा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। श्री निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि आबकारी नीति के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी लाइसेंसधारकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि आबकारी विभाग किसी भी उल्लंघनकर्ता का लाइसेंस रद करने में हिचकिचाएगा नहीं तथा ऐसे दोषियों को भविष्य की अलॉटमेंट/लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। अध्यक्ष ने सभी लाइसेंसधारकों को शराब के निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए। अधिसूचित मूल्य संरचना से किसी भी प्रकार का विचलन आबकारी नीति के संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि प्रभावी निगरानी एवं अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग द्वारा रियल-टाइम स्टॉक अपडेटेशन शुरू किया गया है। सभी लाइसेंसधारकों को निर्धारित प्लेटफॉर्म पर अपने शराब स्टॉक का समय पर एवं सही अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के समापन पर निशांत कुमार यादव ने सभी लाइसेंसधारकों के बीच स्वस्थ एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि, आबकारी नीति के प्रावधानों से किसी भी प्रकार का विचलन अथवा जनहित एवं नियामकीय अनुशासन के प्रतिकूल गतिविधियों से प्रशासन सख्ती और दृढ़ता से निपटेगा।

हरियाणा में 21 नए खेल स्टेडियमों का होगा निर्माण, फर्जी खेल नर्सरियों पर कड़ा एक्शन लें अधिकारी: गौरव गौतम

15 दिन के भीतर जिला खेल अधिकारी खेल नर्सरियों सौंपे ग्राउंड रिपोर्ट, गड़बड़ी मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन खेल सुविधाएं मुहैया करवाना है। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ तेजी से काम कर रही है, जिसके तहत प्रदेश में 21 नए खेल स्टेडियमों का निर्माण करवाया जाएगा। खेल मंत्री आज पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक के दौरान खेल राज्य मंत्री ने फर्जी खेल नर्सरियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी जिला खेल अधिकारी (डीएसओ) अपने-अपने जिलों में चल रही खेल नर्सरियों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर खेल मुख्यालय को भेजें। खेल मंत्री ने चेताया कि इस रिपोर्ट के बाद यदि प्रदेश में कहीं भी कोई फर्जी खेल नर्सरी चलती हुई पाई गई, तो संबंधित जिला खेल अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

श्री गौरव गौतम ने खिलाड़ियों के हितों के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब तक खेल निदेशालय से आधिकारिक बजट जारी नहीं हो जाता, तब तक जिला खेल अधिकारी जिला खेल परिषद के माध्यम से तुरंत खेल उपकरणों व अन्य जरूरी सामान की खरीद सुनिश्चित करें ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खेल मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं और बजट घोषणाओं को पूरी गंभीरता से धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर खेल स्टेडियमों के निर्माण व अन्य लंबित खेल प्रोजेक्टों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के लिए प्रदेश के हर जिले में एथलेटिक्स का सिंथेटिक ट्रैक तैयार किया जाएगा।

डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द 'खेलो हरियाणा ऐप' विकसित करने के निर्देश दिए। इस मोबाइल ऐप में प्रदेश के सभी खिलाड़ियों और खेल स्टेडियमों का पूरा डेटा उपलब्ध होगा, जिससे खिलाड़ी अपने नजदीकी स्टेडियम की जानकारी प्राप्त कर वहां अभ्यास कर सकेंगे। इसके अलावा, खिलाड़ियों को मानसिक रूप से निश्चिंत होकर अभ्यास करने का माहौल देने के लिए उन्होंने 'खिलाड़ी बीमा योजना' का ड्राफ्ट जल्द से जल्द तैयार करने को कहा ताकि खिलाड़ियों को इसका सीधा लाभ मिल सके। खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वर्ष खेल कैलेंडर के अनुसार समय पर सभी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इसके तहत सीएम कप, खेल महाकुंभ, योग और दंगल जैसे प्रमुख खेल आयोजनों को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चयन समितियां इन खेलों के आयोजन से ठीक एक महीने पहले खिलाड़ियों के ट्रायल आयोजित करेंगी। इस अवसर पर खेल विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया, निदेशक श्री पार्थ गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर श्री अश्वनी मलिक व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हालसा ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

नियमित कानूनी सहायता कार्यों से हटकर, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) ने आज एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जो बेहद सफल रहा। शिविर के दौरान कुल 314 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। गर्मी के मौसम में, स्वैच्छिक दान में कमी के कारण अस्पतालों और रक्त बैंकों में अक्सर रक्त की कमी देखी जाती है। यह कमी गंभीर रूप से बीमार रोगियों को बुरी तरह प्रभावित करती है, जिन्हें जीवित रहने के लिए समय पर रक्त की आवश्यकता होती है। इस अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और 14 जून को मनाए जाने वाले ह्लविश्व रक्तदाता दिवसह्व के उपलक्ष्य में, हालसा ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ऐजुकेशन एण्ड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के सहयोग से आज पंचकुला स्थित हालसा के प्रशासनिक भवन में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य श्रीमती किरण सिबल ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया, जो स्वयं विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों में गहरी रुचि रखती हैं। यह नेक पहल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा हालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति दीपक सिबल के प्रेरणादायक मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना और जरूरतमंद एवं गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए रक्त और रक्त-घटकों की उपलब्धता को मजबूत करना था, जिन्हें जीवनरक्षक उपचार की आवश्यकता है। रक्तदाताओं को प्रेरित करते हुए, श्रीमती किरण सिबल ने स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व को एक महान मानवीय कार्य के रूप में रेखांकित किया, जो अनगिनत जिंदगियों को बचाने में सक्षम है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव जगदीप सिंह लोहान ने सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने सामाजिक कल्याण और जनसेवा के प्रति हालसा की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की पहल मानवीय मूल्यों, जनभागीदारी और समाज कल्याण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पंचकूला पुलिस उपायुक्त, सृष्टि गुप्ता और अतिरिक्त उपायुक्त, निशा यादव ने भी इस अवसर पर उपस्थित होकर प्रतिभागियों को रक्तदान के लाभों के बारे में आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। इस शिविर को चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. सुचेत सचदेव के नेतृत्व में 15-20 सदस्यों की एक समर्पित चिकित्सा टीम का सहयोग प्राप्त था। डॉ0 सचदेव ने मई से जुलाई तक के कम रक्त उपलब्धता वाले समय में रक्तदान अभियान आयोजित करने के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से उन संस्थानों द्वारा जिनमें वातानुकूलित इनडोर सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर में गर्मी और मानसून के महीनों के दौरान रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और रक्त की कमी को रोका जा सके।

चंडीगढ़ में फिल्म धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर पर रेप का केस दर्ज

एजेंसी (हि.स.)
चंडीगढ़

फिल्म धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस. जोहर के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर-17 थाना में एक युवती के साथ रेप का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक फाइव स्टार होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और मारपीट करने के साथ गलत तरीके से बंधक बनाकर रखा गया।

युवती का आरोप है कि उसकी ड्रिंक में संदिग्ध नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने जांच के बाद 21 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी। हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते पुलिस ने लंबे समय तक इस केस को सार्वजनिक नहीं होने दिया। हालांकि मामले का खुलासा सोमवार देर शाम को हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद सेक्टर-17 थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में उसे जिला अदालत से जमानत मिल गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिकायतकर्ता युवती चंडीगढ़ के खुड्डा लाहौरा क्षेत्र की रहने वाली है और फिलहाल चंडीगढ़ में रह रही है, जबकि उसका स्थायी पता नई दिल्ली का बताया गया है। शिकायत में युवती ने बताया कि वर्ष 2025 में वह चंडीगढ़ के सेक्टर-10 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान एक शिक्षक के माध्यम से उसका बायोडाटा फिल्म ह्यधुरंधरह्व की टीम तक पहुंचा। इसके बाद 2 सितंबर, 2025 को उसे फिल्म प्रोजेक्ट में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के तौर पर शामिल किया गया।

पीड़िता के अनुसार प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के 4-5 दिन बाद प्रोडक्शन डिजाइनर ने काम की चर्चा के बहाने उसे सेक्टर-17 स्थित एक होटल के कमरे में बुलाया। शिकायत में युवती ने कहा कि 10 सितंबर, 2025 की रात करीब साढ़े 8 बजे वह होटल पहुंची। शुरूआत में उसे लगा कि वहां टीम मीटिंग होगी, लेकिन होटल पहुंचने पर वहां कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था।

संक्षिप्त-समाचार

पंचकूला में अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई

पंचकूला। उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन में डीटीपी श्रीमती बबीता गुप्ता के नेतृत्व में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की टीम द्वारा अर्बन एरिया पंचकूला में बड़ी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव बतौर (बरवाला) में अवैध कॉलोनी में तोड़-फोड़ की गई जिनका एरिया लगभग 2.5 एकड है। जिसमें प्लाटो की निशानदेही व सड़क नेटवर्क को जेसीबी द्वारा धवस्त किया गया। उक्त कार्यवाही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, श्री रमेश कुमार टंडन, एसडीई, पंचायती राज, रायपुररानी, श्री डिम्पी राठी, सहायक नगर योजनाकर, पंचकूला एवं भारी पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई। जानकारी देते हुए डीटीपी श्रीमती बबीता गुप्ता ने बताया कि कोई भी निर्माण या कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति से किसी प्रकार का अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित करता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही जारी रखी जाऐगी। उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना कोई भी निर्माण व अनाधिकृत कॉलोनी विकसित न करें।

मोबाइल ऐप के माध्यम से राशन सब्सिडी सक्रिय करने हेतु विशेष शिविर

चंडीगढ़। सभी राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि खाद्य एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं विधिक माप विज्ञान विभाग, यू.टी. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 28.05.2026 को मालोया (स्मॉल फ्लैट्स), मनीमाजरा (शिवालिक गार्डन के पीछे), खजेड़ी तथा मौली जागरण (विकास नगर) के सामुदायिक केंद्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर उन लाभार्थियों के लिए लगाए जा रहे हैं जिन्होंने राशन सब्सिडी अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त करने हेतु अपनी जानकारी पहले ही जमा करवा दी है, लेकिन अभी तक अपने मोबाइल फोन में मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है। सभी ऐसे लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे अपना आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल फोन साथ लेकर इन शिविरों में पहुंचें ताकि प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना अनिवार्य है। जो लाभार्थी यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे, उनकी सब्सिडी बंद हो सकती है। अतः सभी लंबित लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे इन शिविरों में पहुंचकर प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करें।

शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

चंडीगढ़। निशांत कुमार यादव, आईएएस, उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, रेड क्रॉस चंडीगढ़ ने आज उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़ परिसर में नव-क्रयित शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अमनदीप सिंह भट्टी, सचिव, रेड क्रॉस, पूनम मलिक, नोडल अधिकारी, सुश्री नीना सेठिया, प्रबंध निदेशक, गुरुकुल ग्लोबल स्कूल, डॉ. रीता कालरा, जिला गवर्नर, जगविंदर सिंह बावा, अध्यक्ष तथा कुलविंदर एस. छतवाल, सचिव, रोटरी चंडीगढ़ मिडटाउन भी उपस्थित रहे। यह शव वाहन रोटरी क्लब चंडीगढ़ मिडटाउन तथा गुरुकुल ग्लोबल स्कूल, चंडीगढ़ द्वारा चंडीगढ़ रेड क्रॉस सोसायटी को उपलब्ध करवाया गया है। नव-शामिल यह शव वाहन चंडीगढ़ रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा प्रदान की जा रही आपातकालीन एवं मानवीय सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इसका उपयोग आमजन को आपातकालीन सहायता उपलब्ध करवाने हेतु किया जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए निशांत कुमार यादव, आईएएस, उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, रेड क्रॉस चंडीगढ़ ने कहा कि यह शव वाहन विशेष रूप से चिकित्सकीय आपात स्थितियों एवं आवश्यकता के समय आमजन की सेवा में उपलब्ध रहेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वाहन के शामिल होने से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में और सुधार होगा तथा सामुदायिक कल्याण संबंधी प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

पेक ने छात्र, संकाय एवं स्टाफ खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया सम्मानित

चंडीगढ़। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), चंडीगढ़ में आज डीन स्टूडेंट अफेयर्स कार्यालय द्वारा छात्र, संकाय एवं स्टाफ खेल प्रतियोगिता तथा छात्रों की अंतर-विभागीय खेल प्रतियोगिता के लिए पदक एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में डीन स्टूडेंट अफेयर्स डॉ. डी.आर. प्रजापति, एसोसिएट डीन स्टूडेंट अफेयर्स डॉ. संदीप हरित, एसोसिएट डीन स्टूडेंट अफेयर्स डॉ. मोहित त्यागी, रजिस्ट्रार प्रो. शोभना धीमान तथा स्पोर्ट्स इंचार्ज श्री रविंदर सिंह उपस्थित रहे। गणमान्य अतिथियों ने विजेताओं एवं प्रतिभागियों को सम्मानित किया। छात्रों को फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, रस्साकशी, शॉट पुट, हैमर थ्रो एवं डिस्कस थ्रो सहित विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। वहीं संकाय एवं स्टाफ सदस्यों को क्रिकेट और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। विजेताओं एवं प्रतिभागियों को उनके समर्पण, खेल भावना एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। यह समारोह खेलों को बढ़ावा देने, शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करने तथा छात्रों, संकाय और स्टाफ के समग्र विकास के प्रति पीईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पंचकूला में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए निगम आयुक्त का प्रातः कालीन निरीक्षण अभियान

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

शहर में चल रहे सफाई एवं इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग अभियान के तहत नगर निगम पंचकूला के आयुक्त श्री विनय कुमार, नगर निगम और ढटऊअ की संयुक्त टीमों के साथ सेक्टरों को विभाजित करने वाली प्रमुख सड़कों का नियमित रूप से सुबह के समय निरीक्षण कर रहे हैं। पिछले चार निरीक्षण दौरों में सेक्टर 9/16, 9/10, 10/15, 10/11, 11/14, 11/12, 12/12अ, 4/12, 4/11, 5/8, 5/9 और 5/10 को विभाजित करने वाली सड़कों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान आयुक्त ने सफाई व्यवस्था, बागवानी, निर्माण एवं विध्वंस (उ&ऊ) कचरे के उठान, सड़क नालियों की सफाई, सड़क किनारों (बर्म्स) के रखरखाव और सड़कों की कारपेटिंग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सेक्टरों को विभाजित करने वाली सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कूड़ा, मलबा या कचरा बिना उठाए न पड़ा रहे। जहां भी कमियां पाई गईं, वहां संबंधित अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आयुक्त श्री विनय कुमार ने कहा कि शहर में सफाई मानकों को बहाल करने और उन्हें और बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये निरीक्षण नियमित रूप से किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में सतत निगरानी बनाए रखें और सफाई तथा रखरखाव से जुड़े मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया की हाल ही में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद इन निरीक्षणों का महत्व और बढ़ गया है। नगर निगम ने फील्ड मॉनिटरिंग तेज कर दी है और पंचकूला में पहले से स्थापित सफाई मानकों को फिर से हासिल करने तथा उन्हें और बेहतर बनाने के लिए समन्वित प्रयास शुरू किए हैं। आयुक्त ने कहा कि नगर निगम पंचकूला लगातार निरीक्षण और जमीनी स्तर पर सक्रिय निगरानी के माध्यम से शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के सीईओ ने विभिन्न सेक्टरों में सीएचबी आवासीय इकाइयों में किए गए आवश्यकता आधारित परिवर्तनों की समीक्षा की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय प्रशासक, यू.टी. चंडीगढ़ के निदेर्शों के अनुपालन में, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) की आवासीय इकाइयों में आवश्यकता आधारित परिवर्तनों की जांच एवं सिफारिश हेतु 11.05.2026 को श्री डी. कार्तिकेयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसी क्रम में, श्री डी. कार्तिकेयन ने श्री राजीव मेहता, मुख्य वास्तुकार, यू.टी. चंडीगढ़, श्रीमती मंदीप मेहंदीरेट्टा, वरिष्ठ नगर योजनाकार, शहरी नियोजन विभाग तथा श्रीमती नलिनी शर्मा, वास्तुकार, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के साथ आज शहर के विभिन्न सेक्टरों, जिनमें सेक्टर 40-सी, सेक्टर 43-ए, सेक्टर 43-बी तथा सेक्टर 38 (वेस्ट) शामिल हैं, का दौरा किया तथा स्वतंत्र आवासीय इकाइयों में आवंटियों द्वारा किए गए परिवर्तनों का निरीक्षण किया।

समिति को आवंटियों द्वारा किए गए संशोधनों का आकलन करने, अनुमेय परिवर्तनों की पहचान करने तथा ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया है, जिन्हें संरचनात्मक स्थिरता, अग्नि सुरक्षा, प्रकाश, वेंटिलेशन तथा अन्य आवश्यक नियोजन मानकों से समझौता किए बिना अनुमति दी जा सके। इसके उपरांत सेक्टर 40-सी, 40-डी, 41-ए, 43-ए, 43-बी, 47-डी तथा सेक्टर 13 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने सीएचबी के स्वतंत्र मकानों में आवश्यकता आधारित परिवर्तनों संबंधी अपने सुझाव एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त संबंधित सेक्टरों में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने सीएचबी आवासीय इकाइयों में आवश्यकता आधारित परिवर्तनों की समीक्षा हेतु समिति के गठन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की पहल की सराहना की।

बैठक में श्री सौरभ कुमार अरोड़ा, पीसीएस, सचिव, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड; श्री हितेश पुरी, चेयरमैन, क्रॉफिड; श्री रजत मल्होत्रा, महासचिव, क्रॉफिड; कर्नल गुरसेवक सिंह, अध्यक्ष, आरडब्ल्यूए-एमएचसी, सेक्टर 13; श्री राजेश राय, अध्यक्ष, आरडब्ल्यूए, सेक्टर 43-बी; श्री विक्रम चोपड़ा, अध्यक्ष, आरडब्ल्यूए, सेक्टर 43; श्री राजबीर सिंह बराड़, अध्यक्ष, आरडब्ल्यूए, सेक्टर 38 (वेस्ट) सहित चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एवं चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

निर्देश

आरटीए को नोर्म न पूरे करने वाली स्कूली बसों के ज्यादा से ज्यादा चालान करने के दिए निर्देश

संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों को करें दुरूस्त: उपायुक्त

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होने एनएच, एचएसवीपी, पीएमडीए, पीडब्ल्यूडी को मानसून से पहले पैच वर्क का कार्य पूरा करने व साईन बोर्डों को दुरूस्त करने के निर्देश दिए। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी स्कूल बसों का नियमित निरीक्षण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध हो। उन्होने आरटीए को नोर्म न पूरे करने वाली स्कूली बसों के ज्यादा से ज्यादा चालान करने के साथ साथ सख्त कार्रवाही करने के निर्देश दिए।

पुलिस विभाग को जिले के भीड भाड वाले क्षेत्रों में ट्रकों के आवागमन को कम करने के निर्देश दिए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उपायुक्त ने ट्रको की एंट्री प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए। सचिव आरटीए श्रीमती हैरतजीत कौर ने सभी विभागों द्वारा सडक सुरक्षा व सुरक्षित वाहन पोलिसी पर किए गए कार्यों की रिपोर्ट उपायुक्त के सम्मुख प्रस्तुत की। उपायुक्त ने नगर निगम को सड़क दुर्घटनों में कमी लाने के लिए विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, जो क्रियाशील नहीं है, उन्हें दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करें कि कोई भी ट्रैफिक लाईटस पर भीख न मांगता पाया जाए। इसके अलावा उन्होंने ओल्ड पंचकूला के आस पास खडी होने वाली टैक्सी व प्राइवेट सवारी गाड़ियों के भी चालान करने के निदेश दिए। इन गाडियों के यहां खड़े होने से भीड़ बढ़ती है व दुर्घटना का अंदेशा बना रहता हैं।

उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि विशेष रूप से स्कूल व कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सख्ती के साथ-साथ जागरूकता भी आवश्यक है। इसके लिए समय-समय पर शिक्षण संस्थानों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं।

उन्होंने संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधाएं मिल सकें। साथ ही सड़क निर्माण एजेंसियों को आवश्यकतानुसार साइन बोर्ड लगाने और रोड मार्किंग करने के निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और मृत्यु दर में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन अमूल्य है और दुर्घटना के तुरंत बाद पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर उसकी जान बचाई जा सकती है। उन्होंने निर्देश दिए कि दुर्घटना के बाद पीड़ित को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाए ताकि समय रहते उपचार मिल सके। इस अवसर पर आरटीए सचिव श्रीमती हैरतजीत कौर, एसडीएम पंचकूला श्री चंद्रकांत कटारिया, वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी श्री विशाल कौशिक, एसीपी सुरेंद्र, डीडीपीओ विशाल पराशर, पीएमडीए के एसडीओ, इंस्पेक्टर आशीष, एनएचएआई, एचएसवीपी, सहित शिक्षा विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।